



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14092021-229589
CG-DL-E-14092021-229589

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 264]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 14, 2021/भाद्र 23, 1943

No. 264]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 14, 2021/BHADRA 23, 1943

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2021

अंतिम जांच परिणाम

मामला सं. (एसी) 07/2020

विषय : चीन जन.गण.के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'एक्सल फॉर ट्रेलर्स' के आयातों पर लगाए गए पाटन रोधी शुल्क के कथित उल्लंघन के संबंध में परिवर्तन-रोधी जांच में अंतिम जांच परिणाम ।

1. **फा. सं. 4/11/2020-डीजीटीआर.**—समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (जिसे इसके बाद अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटन-रोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995, (जिसे इसके बाद नियमावली भी कहा गया है), को ध्यान में रखते हुए ।

क. मामले की पृष्ठभूमि

2. यतः, निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें इसके बाद प्राधिकारी भी कहा गया है) ने एक पाटनरोधी जांच में, अपनी अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 14/17/2015-डीजीएडी दिनांक 30.09.2016 के माध्यम से चीन जन.गण के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एक्सल फॉर ट्रेलर्स" (पीयूसी या संबद्ध सामान) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क

लगाने की सिफारिश की थी और वित्त मंत्रालय द्वारा सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 54/2016-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 29.11.2016 के तहत निश्चित पाटन रोधी शुल्क लगाया गया था।

- 3 प्राधिकारी ने सीमा शुल्क आयुक्त (आयात) एनएस-बी जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, न्हावा शेवा, उरण, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र से सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटन-रोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रह तथा क्षति निर्धारण के लिए) संशोधन नियमाली, 1995 के सीमा शुल्क के नियम 26(3) के तहत प्राप्त जानकारी के आधार पर संज्ञान लेते हुए स्वतः एक मामला आरम्भ किया था। जबकि डीजीटीआर को सीमा शुल्क आयुक्त के पत्र में अभिज्ञात किए गए आयातक ने जांच में कोई जवाब दर्ज नहीं किया, मैसर्स.एच.डी. ट्रेलर्स (मूल जांच में एक आयातक) ने एक उत्तर दर्ज किया जिसका प्राधिकारी ने विभिन्न आंकड़ा पहलुओं और कानूनी अनुरोधों पर विश्लेषण किया है। अतः प्राधिकारी ने अपने विश्लेषण को घरेलू उद्योग और आयातक द्वारा दर्ज किए गए आंकड़ों पर आधारित किया है जैसा कि सुसंगत परिवर्चना-रोधी नियमों के तहत अपेक्षित है।
4. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने नियम 26 के तहत जांच आरम्भ की जो निम्नानुसार है;

"26. प्रवर्चना का पता लगाने के लिए जांच की शुरुआत। -

(3) कुछ भी उप नियम (1) में निहित होते हुए भी, निर्दिष्ट प्राधिकारी एक जांच स्वतः आरंभ कर सकते हैं अगर वे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के तहत नियुक्त सीमा शुल्क आयुक्त से प्राप्त जानकारी से संतुष्ट होते हैं या किसी अन्य स्रोत से पता चलता है कि लागू पाटन रोधी शुल्क के उल्लंघन की ओर संकेत करने वाली परिस्थितियों के अस्तित्व के सम्बंध में पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।"

5. जबकि, पाटनरोधी नियमों के नियम 26 के उप नियम 3 के अनुसार सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा दी गई जानकारी का संज्ञान लेते हुए, प्राधिकारी ने अधिसूचना फा. संख्या 4/11/2020-डीजीटीआर-दिनांक 15 सितंबर, 2020 को जांच के तहत उत्पाद (जिसे आगे पीयूआई भी कहा गया है) के आयात के माध्यम से संबद्ध वस्तुओं पर लगाए गए पाटन - रोधी शुल्क के कथित उल्लंघन के अस्तित्व, डिग्री और प्रभाव का निर्धारण करने के लिए और सुसंगत एडी नियमों के अनुसार चीन जन.गण से सीकेडी/एसकेडी स्थिति में पीयूसी के ऐसे आयातों पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के विस्तार की सिफारिश पर भी विचार करने के लिए सम्बद्ध परिवर्चना जांच आरम्भ की।

ख प्रक्रिया

6. सम्बद्ध जांच के संबंध में यहां नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है।
 - i. प्राधिकारी ने चीन जन.गण के दूतावास वार्ड को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटन रोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रह तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 के अनुसार परिवर्चना-रोधी जांच के सम्बंध में अधिसूचित किया।
 - ii. प्राधिकारी ने दिनांक 15 सितंबर, 2020 को भारत के राजपत्र असाधारण में एक सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित किया, जिसमें चीन जनवादी गणराज्य से पीयूआई के आयात के संबंध में परिवर्चना-रोधी जांच आरम्भ की गई थी।
 - iii. प्राधिकारी ने भारत में चीन जन.गण के दूतावास, पीयूसी/पीयूआई के सभी ज्ञात निर्यातकों, रिकोर्डों में उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत में आयातकों को जांच आरम्भ करने नोटिस की एक प्रति अग्रेषित की।
 - iv. प्राधिकारी ने पीयूसी/पीयूआई के निर्यातकों/उत्पादकों को पत्र लिखा और उनसे अनुरोध किया कि वे निर्धारित प्रश्नावली में अपना उत्तर दर्ज करें और निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने विचारों से अवगत कराएं। निर्यातक को भेजा गया पत्र और प्रश्नावली की प्रतियों को ज्ञात निर्यातक/उत्पादक की सूची के साथ चीन जन.गण के दूतावास को भी निर्यातको/उत्पादकों को निर्धारित समय के भीतर प्राधिकारी को उत्तर देने की सलाह देने के अनुरोध सहित भेजा गया।
 - v. प्राधिकारी ने एडी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार चीन जन.गण में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को सुसंगत जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्नावली भेजी:
 - क) गुआंगडोंग एफयूडब्ल्यूए इंजीनियरिंग मैनुफैक्चरिंग कं, लिमिटेड
 - ख) गुआंगडोंग एफयूडब्ल्यूए हेवी इंडस्ट्रीज कं, लिमिटेड
 - ग) शेडोंग जिनशेंग एक्सल मैनुफैक्चरिंग कं, लिमिटेड

- vi. चीन जनवादी गणराज्य के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोध दर्ज नहीं किए हैं। तदनुसार, चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादकों/निर्यातकों को इस जांच में असहयोगी माना जा रहा है।
- vii. एडी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मांगने के लिए भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों / प्रयोक्ताओं को भी प्रश्नावली भेजी गई थी।
- क) किंग कावेरी ट्रेडिंग कंपनी
 - ख) एचडी ट्रेलर्स प्रा. लिमिटेड
 - ग) सतरक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
 - घ) सेफटेक ट्रेलर पार्ट्स एलएलपी
 - ड.) सिनर्जिक ट्रेलर और ऑटो सॉल्यूशंस प्रा. लिमिटेड
 - च) शिवम मोटर्स प्रा. लिमिटेड
 - छ) ब्लैक डायमंड मोटर्स प्रा. लिमिटेड
 - ज) वंदना ट्रेलर्स एंड बाँडी एमएफजी (पी) लिमिटेड
 - झ) एमएस ट्रेलर पार्ट्स एलएलपी
- viii. जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना के उत्तर में, निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने उत्तर दर्ज किया;
- क) एचडी ट्रेलर्स प्रा. लिमिटेड
- ix. मूल जांच के अभिलेखों के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों को भी आरंभिक अधिसूचना भेजी गई थी:
- क) मैसर्स यॉर्क ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट (इंडिया) प्रा. लिमिटेड।
 - ख) मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड
 - ग) मैसर्स अशोक लेलैंड लिमिटेड
 - घ) मैसर्स जेओएसटी इंडिया ऑटो कंपोनेंट प्रा. लिमिटेड।
 - ड.) मैसर्स जीएस ऑटो इंटरनेशनल लिमिटेड
- x. मैसर्स यॉर्क ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट (इंडिया) प्रा. लिमिटेड, जिसने भारत में सम्बद्ध वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक होने का दावा किया है, ने जांच शुरुआत का समर्थन किया और संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई तथा प्राधिकारी को वर्तमान जांच के सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उन्हें घरेलू उद्योग के रूप में मानने के लिए अनुरोध किया। अन्य उत्पादकों ने वर्तमान जांच का न तो समर्थन किया है और न ही विरोध किया है।
- xi. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अन्य पक्षों को प्रस्तुत किए गए प्रमाणों के अगोपनीय संस्करण को ई-मेल के माध्यम से अनुरोधों का आदान-प्रदान करने के निर्देश के रूप में उपलब्ध कराया क्योंकि चल रही महामारी के कारण सार्वजनिक फ्राइल के भौतिक सत्यापन की अनुमति नहीं है। सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को इस अंतिम जांच परिणाम में सुसंगत मानी गई सीमा तक ध्यान में रखा गया है।
- xii. गोपनीयता के आधार पर हितबद्ध पक्षों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावे को स्वीकार कर लिया है, जहां कहीं भी आवश्यक हो और ऐसी जानकारी को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसका खुलासा नहीं किया गया है। जहां भी संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षों को निर्देश दिया गया था कि वे जानकारी का पर्याप्त अगोपनीय संस्करण उपलब्ध कराएं।

- xiii. आवश्यक समझी जाने वाली सीमा तक हितबद्ध पक्षकारों से अधिक जानकारी मांगी गई थी।
- xiv. अप्रैल, 2019 से मार्च, 2020 (12 महीने) तक की अवधि के लिए जांच की गई थी (जिसे इसके बाद "जांच की अवधि" या "पीओआई" भी कहा गया है)। क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जांच में 2016-17, 2017-18, 2018-19 और जांच की अवधि को शामिल किया गया।
- xv. वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से पिछले चार वर्षों के दौरान पीयूसी और पीयूआई के आयातों का विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, जिसमें जांच की अवधि भी शामिल है, और यह प्राधिकारी को प्राप्त हुआ था। प्राधिकारी ने डीजीसीआई एण्ड एस आयात आंकड़ों का उपयोग आयात की मात्रा और क्षति विश्लेषण के मूल्य की गणना के लिए किया है।
- xvi. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षों को 10 दिसंबर, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। सभी पक्षों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने लिखित अनुरोध प्रस्तुत करें और मौखिक सुनवाई के बाद लिखित अनुरोध प्रस्तुत करें। निर्दिष्ट प्राधिकारी के बदल जाने के कारण, दिनांक 22 फरवरी, 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक और मौखिक सुनवाई हुई और सभी हितबद्ध पक्षकारों को लिखित और प्रत्युत्तर अनुरोध, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने का और अवसर दिया गया।
- xvii. जहां कहीं किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच के दौरान आवश्यक सूचना तक पहुंच से इंकार किया है या अन्यथा प्रदान नहीं किया है, या जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डाली है, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपनी टिप्पणी दर्ज की है।
- xviii. दिनांक 09.08.2021 को एक प्रकटीकरण विवरण जारी किया गया था जिसमें हितबद्ध पक्षकारों को निर्दिष्ट प्राधिकारी के विचाराधीन आवश्यक तथ्यों का खुलासा किया गया था और प्रकटीकरण विवरण पर टिप्पणी, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 12.08.2021 तक का समय दिया गया था। हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटन पश्चात टिप्पणियों की जांच की गई है और इन अंतिम जांच परिणामों के संगत पैराओं पर उचित रूप से विचार किया गया है।
- xix. *** इन अंतिम जांच परिणामों में एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना को प्रस्तुत किया गया है, और इस प्रकार नियमों के तहत प्राधिकारी द्वारा इस पर विचार किया गया है।
- xx. अमरीकी डालर को भारतीय रुपये में बदलने के लिए पीओआई के लिए मानी जाने वाली विनिमय दर 1अमरीकी डालर=71.65 रुपए है।

ग. विचाराधीन उत्पाद/जांच के तहत उत्पाद और सामान वस्तु

ग.1 विचाराधीन उत्पाद

- 7. चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एक्सेल फार ट्रेलर्स" (जिसे इसके बाद पीयूसी या संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) में विचाराधीन उत्पाद वही है जो पिछली जांच में परिभाषित है। यह सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की पहली अनुसूची के सीमा शुल्क टैरिफ 87169010 के अंतर्गत आता है। चीन जन.गण से पीयूसी के आयात पर पाटन रोधी शुल्क दिनांक 28.11.2021 तक लागू है।
- 8. संबद्ध वस्तुओं का निर्माण और बिक्री विभिन्न रूपांतरों में की जाती है। तथापि, इन सभी प्रकारों की मूल उत्पाद विशेषताएँ और अंतिम उपयोग समान रहता है और इस तरह के सभी प्रकार के ट्रेलर एक्सल को पीयूसी के दायरे में शामिल किया गया है। सभी ऐसे रूपांतर अनिवार्य रूप से तुलनीय बुनियादी विशेषताओं और समान कार्य/उपयोगों के विचारार्थ एक समरूप उत्पाद बनाते हैं।

ग.2 जांच के तहत उत्पाद

- 9. जांच के अधीन उत्पाद (बाद में पीयूआई के रूप में भी जाना जाता है) सीकेडी (पूर्ण नॉक डाउन)/एसकेडी (सेमी नॉक डाउन) स्थितियों में सम्बद्ध वस्तु है जिसे 'ट्रेलर एक्सल के हिस्से' के रूप में घोषित करके आयात किया जा रहा है और जिसे कथित तौर पर चीन जन.गण से पीयूसी के आयात पर लागू पाटन-रोधी शुल्क की परिवंचना कर रहा है

ग. 3 घरेलू उद्योग के विचार

10. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के स्कोप और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क) पीयूसी और पीयूआई को जांच की आरम्भ में अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है और मामले के तथ्य यह स्पष्ट करते हैं कि पीयूआई सीकेडी/एसकेडी स्थिति में पीयूसी के आयात के अलावा और कुछ नहीं है।
- ख) ट्रेलरों के लिए एक्सल को सीकेडी (पूर्ण नॉक डाउन)/एसकेडी (सेमी नॉक डाउन) स्थिति में, इसे ट्रेलर एक्सल के हिस्से के रूप में घोषित करके 'एक्सल फॉर ट्रेलर्स' पर एडीडी से बचने के आशय से आयात किया जा रहा है और अपनाई गई पीयूआई की परिभाषा पूरी तरह से कुछ आयातकों द्वारा अपनाई जा रही ऐसी प्रथाओं को दर्शाता है।
- ग) पीयूसी और पीयूआई की परिभाषा यह स्पष्ट करती है कि 'एक्सल फॉर ट्रेलर्स' के आयात के समय लागू पीयूआई वारंट एडीडी के आयात को पीयूआई के ऐसे आयातों तक बढ़ाया जाएगा।
- घ) पीयूआई सीकेडी/एसकेडी स्थिति में पीयूसी के अलावा और कुछ नहीं है। ऐसे आयातों का विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क के परिवर्तन के अलावा कोई अन्य औचित्य नहीं है। इसके बाद पीयूआई को बहुत कम मूल्यवर्धन के साथ पीयूसी के रूप में असेंबल किया जाता है कि परिवर्तन बहुत स्पष्ट है।
- ड.) एचडी ट्रेलरों ने एक तर्क देकर कि वे सिंगल पीस सीमलेस बीम का आयात कर रहे हैं, जो कि उनके अनुसार एक बेहतर उत्पाद है, क्योंकि भारत में उपलब्ध बीम 3 पीस वेल्डेड बीम हैं, जो उचित ठहराने का प्रयास कर रहे हैं। विवाद का कोई आधार या योग्यता नहीं है।
- च) सिंगल पीस बीम को किसी भी तरह से बेहतर उत्पाद नहीं माना जा सकता है और यह भारत जैसे देशों में बने एक्सल के साथ स्पष्ट रूप से प्रतिस्पर्धी उत्पाद है। सिंगल पीस बीम का ग्लोबल मार्केट में प्रमुखता से उपयोग नहीं किया जाता है। यह केवल चीनी निर्माताओं द्वारा उपयोग किया जाता है। कोई भी भारतीय ट्रक निर्माता भारत में इस सिंगल पीस बीम तकनीक का उपयोग नहीं करता है। श्री पीस वेल्डेड बीम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सिद्ध हैं। इसके अलावा टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड जैसे बड़े ओईएम अपने वाणिज्यिक वाहन नॉन ड्राइव एक्सल/टैग एक्सल और ट्रेलर एक्सल में इन 3 पीस वेल्डेड बीम का उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार, ऐसे उत्पाद के आयात का उद्देश्य अभी भी पाटनरोधी शुल्क की चोरी है और ऐसे आयातों के लिए कोई अन्य वास्तविक कारण नहीं है। सीमलेस सिंगल पीस बीम का आयात किसी भी तरह से परिवर्तन को सही नहीं दर्शाता जैसा कि वर्तमान मामले में किया जा रहा है।

ग. 4 विरोधी हितबद्ध पक्षों के विचार

11. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों के विचारों का सार नीचे दिया गया है:

- क) यह एच डी ट्रेलरों प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उनके प्रश्नावली प्रतिउत्तर में प्रस्तुत किया गया है कि वे केवल धुरी बीम, कैम दस्ता, कैम सेट, स्लैक एडजस्टर, हब कैप आयात करते हैं।
- ख) एचडी ट्रेलर्स प्राइवेट लिमिटेड की गतिविधि स्थानीय सामग्री के साथ आयातित पीयूआई को उनके आईक्यूआर में प्रस्तुत किए गए पीयूसी का उत्पादन करने के लिए एकत्र करना है।
- ग) एक्सल बीम ट्यूब एक्सल के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बाकी निर्माताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली ट्यूब में वेल्डिंग द्वारा जुड़े एक से अधिक भाग होते हैं। जिन ट्यूबों का हम आयात कर रहे हैं वह सीमलेस है और इस प्रकार अधिक शक्तिशाली है। कोई भी भारतीय निर्माता सीमलेस ट्यूब नहीं बनाता है। इसी प्रकार आयातित सामग्री का हब कैप की अद्वितीय डिजाइन अब तक के स्वदेशी उत्पाद से बेहतर है। इन कारणों से आयातित उत्पाद योर्क की तुलना में उच्च मूल्य पर बेचा जाता है।

ग.5 प्राधिकारी द्वारा जांच

12. वर्तमान जांच चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'एक्सल फॉर ट्रेलर्स' के आयात पर लगाए गए शुल्कों से संबंधित एक परिवर्तन-रोधी जांच है। इसलिए, विचाराधीन उत्पाद के स्कोप में, जैसा कि अंतिम समाम पाटन रोधी जांच में परिभाषित है, वर्तमान जांच के लिए भी लागू है।

13. चीन जनवादी गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'एक्सल फॉर ट्रेलर्स' में विचाराधीन उत्पाद वही है जो पिछली जांच में परिभाषित है अर्थात् यह पहली अनुसूची के सीमा शुल्क टैरिफ प्रमुख 87169010 सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अंतर्गत आता है तथापि जांच के तहत उत्पादों का उपरोक्त उक्त वर्गीकरण को अत्यधिक कम मूल्य वर्धन के साथ पीयूसी के रूप में एकत्र किया गया है कि परिवर्चना प्रत्यक्ष है। चीन जन गण से आयात पर पाटन रोधी शुल्क दिनांक 28.11.2021 तक लागू है।
14. संबद्ध वस्तुओं का निर्माण और बिक्री विभिन्न रूपों में की जाती है। तथापि, इन सभी प्रकारों की मूल उत्पाद विशेषताएँ और अंतिम उपयोग समान रहता है और इस तरह के सभी प्रकार के ट्रेलर एक्सल को पीयूसी के स्कोप में शामिल किया गया है। ऐसे सभी रूप अनिवार्य रूप से तुलनीय बुनियादी विशेषताओं और समान कार्यों/उपयोगों के साथ एक समरूप उत्पाद का निर्माण करते हैं।
15. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन.गण से पीयूसी के आयात पर लागू पाटन रोधी शुल्क की कथित तौर पर सीकेडी (पूर्ण नाक डाउन)/एसकेडी (अर्ध नाक डाउन) स्थिति में पीयूसी के आयात और उन्हें ट्रेलर एक्सल के भाग 'के' रूप में की घोषणा द्वारा के द्वारा परिवर्चना की जा रही है। आयात आंकड़ों के अनुसार, पीयूआई आयात में भाग जैसे धुरी बीम, कैम दस्ता, कैम सेट, स्लैक समायोजक, हब कैप, ब्रेक ड्रम आदि कवर किया जाता। यह उपलब्ध जानकारी से नोट किया गया है जिसमें कह गया है कि आयातित पीयूआई को पीयूसी का निर्माण करने के लिए जोड़ा जा रहा है और अलग भागों का कोई अन्य ज्ञात उपयोग नहीं है। चूंकि पीयूआई के आयात का उद्देश्य पीयूसी के निर्माण के लिए संयोजन और उसके केवल इस तरह के जुड़ाव ले लिए हैं, इसलिए यह पीयूसी पर मौजूदा पाटन-रोधी शुल्क के परिवर्चना कर रहा है।
16. प्राधिकारी रिकॉर्ड में जानकारी से नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद सम्बद्ध देशों से आयातित सामान के लिए "समान वस्तु" की तरह है। भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद तकनीकी विशिष्टताओं, कार्यों या अंतिम उपयोग उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन और माल के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। दोनों तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं। उपभोक्ता इन दोनों का परस्पर उपयोग कर रहे हैं।
17. प्राधिकारी का मानना है कि चीन जन.गण से आयात किया जा रहा पीयूआई और कुछ नहीं बल्कि सीकेडी (पूर्ण नाक डाउन)/एसकेडी (सेमी नाक डाउन) स्थिति में 'एक्सल फॉर ट्रेलर्स' के आयात को ट्रेलर एक्सल के हिस्से के रूप में घोषित कर रहा है।
18. विरोधी पक्ष के इस तर्क के संबंध में कि एक्सल बीम आयात एकल सीमलेस ट्यूब से बना है और भारतीय उत्पादकों द्वारा आपूर्ति किए गए श्री-पीस बीम की तुलना में एक बेहतर उत्पाद है, प्राधिकारी उपलब्ध जानकारी से नोट करते हैं कि उक्त सिंगल पीस बीम को विचाराधीन उत्पाद में शामिल उत्पाद से भिन्न उत्पाद के रूप में नहीं माना जा सकता है। सिंगल पीस बीम या वेल्डेड बीम से निर्मित ट्रेलरों के लिए एक्सल तुलनीय उत्पाद हैं और उन्हें भारतीय निर्माता द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार दूसरे के लिए प्रत्यक्ष विकल्प के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार, विवाद कि पीयूसी से एक अलग उत्पाद, जो पाटन-रोधी शुल्क के अधीन है के रूप में, पीयूसी / पीयूआई के स्कोप से एक सिंगल पीस बीम को हटाने का कोई आधार नहीं है।

घ. घरेलू उद्योग और स्टैंडिंग का स्कोप

घ.1 घरेलू उद्योग के विचार

19. मेसर्स यॉर्क ट्रांसपोर्ट इन्फ्रिमेंट (इंडिया) प्रा. लिमिटेड ने घरेलू उद्योग और स्थिति के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
 - क. यह अनुरोध किया गया है कि मेसर्स यॉर्क ट्रांसपोर्ट इन्फ्रिमेंट (इंडिया) प्रा. लिमिटेड वर्तमान जांच के प्रयोजनों के लिए घरेलू उद्योग के रूप में माना जाता है क्योंकि यह सबद्ध माल के भारतीय उत्पादन का प्रमुख अनुपात रखता है और यह पूरी तरह से वर्तमान जांच का समर्थन करता है।
 - ख. मूल जांच में भी कंपनी को घरेलू उद्योग माना गया था। यॉर्क द्वारा अपनाए गए कुल भारतीय उत्पादन के अनुमान का आधार, प्राधिकारी के मूल निष्कर्षों के अनुरूप है और यह स्पष्ट होगा कि संबद्ध वस्तुओं के भारतीय उत्पादन में यॉर्क का बड़ा हिस्सा है।

- ग. कंपनी ने यह भी प्रमाणित किया है कि उसने वर्तमान जांच के लिए भारत और चीन जन.गण में सुसंगत संबंधित पक्षों पर घोषणाओं के साथ चीन जन.गण से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है। चीन जन.गण के अलावा अन्य देशों में किसी भी संबंधित पक्षों का विवरण भी कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध हैं, तथापि इस तरह के विवरण है वर्तमान जांच में कोई प्रासंगिकता नहीं है।
- घ. एचडी ट्रेलर्स प्राइवेट लिमिटेड को घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं माना जा सकता है और एचडी ट्रेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के पीयूसी के घरेलू उत्पादक के रूप में उसके दावों के आधार को जांच की आवश्यकता है।
- ड. एचडी ट्रेलर्स प्राइवेट लिमिटेड सबसे बड़ा आयातक है जो एक असेम्बलिंग सुविधा और एचडी ट्रेलर्स के व्यापार की प्रकृति के आरम्भ करके एडीडी के परिवर्चना को बनाये रखा है, से स्पष्ट है कि वे खुले तौर पर शुल्क के परिवर्चना में कार्यरत है।
- च. एचडी ट्रेलर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पीयूआई के आयात में वृद्धि से ऐसी व्यवस्था का पता चलता है और यह भी नोट करने की आवश्यकता है कि पीओई द्वारा पीयूसी का आयात शून्य हो गया है, जैसाकि उल्लिखित कम्पनी द्वारा घोषित किया गया है।
- छ. यह प्रमाणित करना एचडी ट्रेलर्स का कर्तव्य है कि वह परिवर्चना गतिविधियों में संलग्न नहीं है और जब तक और जब तक यह साबित नहीं हो जाता, वह घरेलू उद्योग के भाग के रूप में नहीं माना जा सकता है। कंपनी ने दावा किया है कि वे पीयूआई को शुल्कों का विस्तार करने के पक्ष में हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शुल्कों का लाभ कम न हो। तथापि, एचडी ट्रेलर्स की प्रतिक्रिया से पता चलता है कि वे प्रमुख भागों का आयात कर रहे हैं और ऐसे मामले में परिवर्चना अस्वीकार असंभव होगा।
- ज. सम्बद्ध वस्तुओं के भारतीय निर्माता के रूप में एचडी ट्रेलर्स के दावे के असलियत की जांच करने के लिए प्राधिकारी को सम्बद्ध उत्पाद के उत्पादन के लिए यॉर्क और एचडी ट्रेलर्स द्वारा किए गए निवेशों और संयंत्र तथा मशीनरी एवम दोनों कंपनियों द्वारा तैनात किए गए अन्य विवरण के व्यौरों की तुलना और जांच करनी होगी ताकि दावों की प्रामाणिकता को सत्यापित किया जा सके। जैसा कि यह मत है, एचडी ट्रेलर्स द्वारा मशीनों के नामों की सूची के अलावा ऐसी कोई जानकारी प्रदान नहीं की गई है जिसका खुलासा नहीं किया गया है और हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं दे सकते हैं।
- झ. एचडी ट्रेलर्स द्वारा किया गया निवेश स्पष्ट रूप से असेम्बलिंग इकाई के लिए है और यॉर्क की तरह सम्बद्ध वस्तुओं के उत्पादन की कोई क्षमता नहीं है और एक्सेल फोर ट्रेलर्स के सदाशयी निर्माता के रूप में कंपनी द्वारा ऐसा कोई निवेश नहीं किया गया है।
- ञ. यॉर्क स्थायी आवश्यकता को पूरा करता है और एडी नियमों के क्षेत्र में घरेलू उद्योग का गठन करता है।

घ.2 अन्य हितबद्ध पक्षों के विचार

20. घरेलू उद्योग की स्थिति और कार्यक्षेत्र के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क) मेसर्स यॉर्क ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट (इंडिया) लिमिटेड का अपने स्वयं के समूह की कंपनियों के साथ व्यापारिक संबंध हैं, जिनके बीच आयात और निर्यात होता है। इसके अलावा, अन्य संस्थाएं भी उनके साथ जुड़ गई हैं और एक संघ का गठन किया है, तथापि कानूनी रूप से ऐसी व्यवस्था को ऐसे संघों की घोषणा की कानूनी आवश्यकता से बाहर रखा गया है। इसके परिणामस्वरूप अलग-अलग नामों में भागों का आयात होता है और अन्य संस्थाओं द्वारा उसी की उपयोगिता होती है।
- ख) $10\% \times 1 + 80\% \times 2 + 10\% \times 3$ के सूत्र को लागू करके एक्सेल की आवश्यकता की गणना सही नहीं है। लागू किया जाने वाला फॉर्मूला $1\% \times 1 + 30\% \times 2 + 69\% \times 3$ है। इस सही फॉर्मूले को लागू किए जाने से यॉर्क का हिस्सा काफी हद तक बदल जाएगा।
- ग) एचडी ट्रेलर्स द्वारा निर्मित उत्पाद ट्रेलर एक्सल के इनपुट के 69% अब स्वदेशी हैं और इसलिए हम अनुरोध करते हैं कि एचडी ट्रेलर्स को भारतीय विनिर्माता के रूप में माना जा सकता है न कि आयातक के रूप में।
- घ) एचडी ट्रेलर्स प्रा. लिमिटेड ने ट्रेलर एक्सल पर एडीडी लगाने से बहुत पहले ट्रेलर एक्सल के निर्माण के लिए अपना कारखाना स्थापित किया है और अब ट्रेलर एक्सल के लगभग 69 % घटक स्वदेशी हैं।

ब.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

21. चूंकि वर्तमान जांच सीमा शुल्क प्राधिकारी से प्राप्त सूचना के आधार पर आरम्भ की गई थी, इसलिए जांच आरम्भ करने के स्तर पर वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग की पहचान आवश्यक नहीं थी। तथापि, पिछली जांच के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं के ज्ञात उत्पादकों को जांच के सम्बंध में सूचित किया गया था और ऐसे पक्षों से प्रासंगिक जानकारी मांगी गई थी। यह नोट किया गया है कि केवल एम/एस यॉर्क परिवहन उपकरण (इंडिया) लिमिटेड ने जांच आरम्भ होने की नोटिस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है और वर्तमान जांच उनमें से इस प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग के रूप में माने जाने हेतु अनुरोध किया। कंपनी ने आवश्यक जानकारी भी प्रदान की है। यह भी नोट किया गया है कि मेसर्स यॉर्क ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट (इंडिया) लिमिटेड को पिछली जांच में संबद्ध वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग के रूप में निर्धारित किया गया था।

22. यह नोट किया गया है कि पाटनरोधी नियमों के नियम 26(1) और 26(3) को निम्नानुसार पढ़ा जाता है:

26(1): जैसा कि यहां नीचे दिया गया है, को छोड़कर, निर्दिष्ट प्राधिकारी घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से कोई लिखित आवेदन पत्र प्राप्त होने पर अधिनियम की धारा 9 क के तहत लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की तथाकथित प्रवंचना की मौजूदगी और उसका प्रभाव निर्धारित करने के लिए जांच शुरू कर सकते हैं।"

नियम 26 (3): कुछ भी होते हुए भी उप नियम (1) में निहित, निर्दिष्ट प्राधिकारी एक जांच आरंभ कर सकते हैं स्वतः स्वप्रेरणा यदि इसमें नियुक्त सीमा शुल्क आयुक्त से प्राप्त जानकारी से संतुष्ट हो जाता है सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) या कोई अन्य स्रोत जो लागू पाटनरोधी शुल्क के उल्लंघन की ओर इशारा करने वाली परिस्थितियों के अस्तित्व के सम्बंध में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है।

23. सीमा शुल्क (आयात)के आयुक्त, न्हावा एस एच ईवा से प्राप्त जानकारी के आधार पर नियम 26(3) के तहत प्राधिकारी ने स्वतः सम्बद्ध जांच आरम्भ की।
24. इस तर्क के संबंध में कि मेसर्स यॉर्क ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट (इंडिया) लिमिटेड का आयातकों/निर्यातकों से संबंध की जांच की जानी चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मेसर्स यॉर्क ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट (इंडिया) लिमिटेड ने प्रमाणित किया है कि उन्होंने चीन जन.गण से स्वयं या किसी भी संबंधित पक्ष के माध्यम से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है।
25. एचडी ट्रेलर प्राइवेट लिमिटेड को घरेलू उद्योग के स्कोप में विचार करने के उनके दावे के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि कंपनी द्वारा ऐसे दावों को प्रमाणित करने के लिए कोई पर्याप्त जानकारी प्रदान नहीं की गई है। कंपनी ने आयातक प्रश्नावली प्रारूप में त्रुटिपूर्ण जानकारी दर्ज की है जो दर्शाती है कि कंपनी पूरी क्षति अवधि में चीन जनवादी गणराज्य से पीयूआई का आयात करती रही है। कंपनी का आचरण पीयूआई के आयातक का रहा है और एचडी ट्रेलर्स प्रा. लि. को घरेलू उद्योग के स्कोप में नहीं माना जा सकता है।
26. मेसर्स एचडी ट्रेलर्स प्रा.लि. के तर्कों के संबंध में, कि घरेलू उत्पादक द्वारा दावा किया गया कुल भारतीय उत्पादन और ऐसे उत्पादन की गणना के लिए अपनाई गई पद्धति सही नहीं है, प्राधिकारी इस मामले की मूल जांच में अपनाई गई ऐसी गणनाओं पर अपने निष्कर्षों का स्मरण करते हैं। तब अपनाई गई कार्यप्रणाली को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है और वर्तमान मामले में भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया गया है क्योंकि उपरोक्त कार्यप्रणाली को बदलने के लिए किसी भी पक्ष द्वारा कोई वास्तविक तथ्य नहीं जोड़े गए हैं।

"यह भी देखा गया है कि कुल भारतीय उत्पादन के सम्बंध में जानकारी सार्वजनिक डोमेन में आसानी से उपलब्ध नहीं है और आवेदक ने कुल भारतीय उत्पादन और अकेले आवेदक और ऐसे अनुमानित कुल भारतीय में समर्थक के साथ उत्पादन के हिस्से का अनुमान लगाने के लिए एक पद्धति तैयार की है। इसने प्राइम मूवर्स के उत्पादन डेटा पर भरोसा किया है, जिसमें ट्रेलर संलग्न हैं, जिसमें संबद्ध वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, जिसे सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरर्स (सियाम) द्वारा भारत में संबद्ध वस्तुओं की आवश्यकता को प्राप्त करने और वापस भारत में संभावित घरेलू उत्पादन की गणना करने के लिए एक आधार के रूप में प्रकाशित किया जाता है। एसआईएम डेटा संपूर्ण जांच अवधि के लिए उपलब्ध कराया गया है। सियाम द्वारा रिपोर्ट किए गए प्राइम मूवर्स की कुल संख्या में से, आवेदक ने लगभग 10% को इसमें 1 एक्सल की आवश्यकता के रूप में माना है और 80% को 2 एक्सल की आवश्यकता के रूप में और शेष 10% को 3 एक्सल की आवश्यकता के रूप में माना है। पीओआई के लिए विचार किए गए प्राइम मूवर्स की संख्या में विभिन्न प्रकार के ट्रेलर शामिल थे जैसे कि 35 टन, 40 टन आदि....."

ड. पाटन का आकलन - कार्यप्रणाली तथा सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटन मार्जिन का निर्धारण**ड.1 सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटन मार्जिन का निर्धारण****ड.1.1. पीयूआई का सामान्य मूल्य**

27. जैसा कि है ऊपर बताया गया है, पीयूआई सीकेडी/एसकेडी स्थिति में पीयूसी के आयात के अलावा और कुछ नहीं। ऐसे परिदृश्य में पीयूआई और पीयूसी दोनों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया है। चीन जनवादी गणराज्य के किसी भी निर्यातक ने वर्तमान जांच आरम्भ करने पर प्रतिक्रिया नहीं दी है और प्राधिकारी सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना को अपनाने के लिए बाध्य हैं। तदनुसार, सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में उत्पादन लागत के अनुमानों के आधार पर किया जाता है, जिसे उचित लाभ जोड़कर घरेलू उद्योग की बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक लागतों को शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित किया जाता है। चीन जन.गण के लिए पीयूआई और पीयूसी के लिए इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे तालिका में दिया गया है;

28. अधिनियम के धारा 9क(1) (ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है;

- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख) उपधारा- (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उद्गम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

चीनी उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति

29. विश्व व्यापार संगठन में चाइनीज एसेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान है:

"जीएटीटी का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, 1994 ("पाटनरोधी समझौता") के अनुच्छेद-VI के कार्यान्वयन पर समझौता तथा एससीएम समझौता निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्यों में चीन मूल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगे:

(क) जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी समझौते के तहत मूल्य की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:

- (i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।
- (ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-

साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

- (ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के सम्बंध में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।
- (ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।
- (घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

30. यह नोट किया गया है कि अनुच्छेद 15 (क) (ii) में निहित प्रावधान दिनांक 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं, जबकि असेशन प्रोटोकॉल प्रावधान 15 (क)(i) के तहत दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ के अनुच्छेद 2.2.1.1 के तहत भारत के नियमों के अनुबंध। के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति का दावा करने पर पूरक प्रश्नावली में प्रदान की जाने वाली जानकारी/डेटा के माध्यम से संतुष्ट होने के लिए की आवश्यकता होती है। यह नोट किया गया है कि चूंकि चीन जन. गणर के उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्धारित प्रपत्र और तरीके से पूरक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है तथा उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए सामान्य मूल्य की गणना नियमों के अनुबंध। के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार की जानी चाहिए।
31. तदनुसार, संबद्ध देश के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य नियमों के अनुबंध। के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया गया है जो निम्नानुसार है।

"गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की कीमत अथवा संरचित मूल्य, अथवा किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव न हो, अथवा अन्य किसी समुचित आधार पर किया जाएगा जिसमें भारत में समान वस्तु के लिए वास्वित रूप से संदत्त अथवा भुगतान योग्य कीमत, जिनमें यदि आवश्यक हो तो लाभ की समुचित गुंजाइश भी शामिल की जाएगी निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे समुचित देश का चयन उचित तरीके से किया जाएगा जिसमें संबंधित देश के विकास के स्तर तथा प्रश्रुत उत्पाद का ध्यान रखा जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना का भी ध्यान रखा जाएगा। जहां उचित हो, उचित समय सीमा के भीतर किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में की गई जांच पर भी ध्यान दिया जाएगा। जांच से संबंधित पक्षों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त प्रकार से चयन के बारे में बिना किसी विलंब के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित अवधि प्रदान की जाएगी।"

32. प्राधिकारी नोट करते हैं कि गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माने जाने वाले देश के लिए सामान्य मूल्य की गणना एडी नियमों के अनुबंध-। के पैरा 7 और 8 के अनुसार की जानी चाहिए। वर्तमान मामले में, किसी भी निर्यातक ने उत्तर नहीं दिया है और कोई निर्यातक प्रश्नावली उत्तर दर्ज नहीं किया है और इसलिए प्राधिकारी नोट करते हैं कि एडी नियमों के अनुबंध-। के पैरा 7 के तहत विकल्पों का पता लगाने की आवश्यकता है।

33. पैरा 7 सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए एक पदानुक्रम निर्धारित करता है और यह प्रदान करता है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर किया जाएगा, या ऐसे तीसरे देश से अन्य देशों में कीमत, जिसमें भारत, शामिल हैं या जहां यह संभव नहीं है, किसी अन्य उचित आधार पर, जिसमें समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में भुगतान या देय मूल्य शामिल है, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए यदि आवश्यक हो तो विधिवत समायोजित किया गया है। इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि सामान्य मूल्य का निर्धारण अनुलग्नक 7 के अंतर्गत प्रदान किए गए विभिन्न अनुक्रमिक विकल्पों को ध्यान में रखते हुए किया जाना अपेक्षित है।
34. घरेलू उद्योग ने पीयूआई और पीयूसी के लिए पाटन मार्जिन निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग की लागत को अपनाकर निर्मित आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है। एक विकल्प के आधार के रूप में, सामान्य मूल्य अन्य देशों से भारत में पीओआई के आयात के आधार पर ऐसा भी प्रस्तावित किया गया। यह है इस संबंध में यह नोट किया गया है कि अन्य देशों से पीओआई का कोई महत्वपूर्ण आयात नहीं था और आयात जानकारी केवल कुछ घटकों के लिए उपलब्ध है। यहां तक कि घरेलू उद्योग ने भी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य के सम्बंध में या ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को कीमत के सम्बंध में कोई जानकारी नहीं दी।
35. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षों के तर्कों को नोट किया है और नोट किया है कि पैरा 7 के पहले परंतुक को लागू करने पर विचार करने के लिए किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा पर्याप्त सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है और न ही इसके लिए प्राधिकारी के पास कोई सूचना उपलब्ध है।
36. जहां तक पैरा 7 में अगले परंतुक का संबंध है, प्राधिकारी डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों के अनुसार आयात जानकारी से नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान चीन जन.गण के अलावा अन्य देशों से आयात केवल नगण्य थे और सभी घटकों के लिए आयात उपलब्ध नहीं है। संबद्ध उत्पादों का आयात मुख्य रूप से केवल चीन जनवादी गणराज्य से हुआ था। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि ऐसे तीसरे देश से संबद्ध वस्तुओं के निर्यात के आधार पर किसी तीसरे देश से अन्य देशों को कीमत पर कोई विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसलिए, दूसरे देश को पीयूसी के निर्यात पर पर्याप्त जानकारी के अभाव में, प्राधिकारी पैरा 7 पदानुक्रम के विकल्प 3 को नहीं अपना सकता है।
37. अतः, प्राधिकारी ने उचित संशोधनों के साथ भारतीय उत्पादन लागत (सीओपी) के आधार पर निर्मित सामान्य मूल्य को उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में भुगतान या देय मूल्य के रूप में माना है।
38. सामान्य मूल्य का निर्धारण करते समय अपनाए जाने वाले पदानुक्रम के संबंध में, प्राधिकारी ने निम्नलिखित चरणों का पालन किया है:
 - क) न तो पीयूसी और न ही पीयूआई का कोई समर्पित सीमा शुल्क वर्गीकरण है। अतः, किसी भी एचएस कोड के निर्यात आंकड़ों पर विचार करके बाजार अर्थव्यवस्था तीसरे देश से निर्यात के आधार पर निर्मित सामान्य मूल्य प्राप्त नहीं किया जा सका। यह भी संभव नहीं था क्योंकि मौजूदा जांच में किसी भी हितबद्ध पक्ष ने इसके लिए कोई आंकड़ा दर्ज नहीं किया है।
 - ख) भारत सहित तीसरे देश से दूसरे देश में पीयूआई की कीमतों की जांच की गई और यह पाया गया कि लगभग 7 पीयूआई प्रकारों की पहचान की गई थी, आयात केवल लगभग 3 प्रकारों के लिए देखा गया था और पीओआई के दौरान पीयूआई में शामिल शेष 4 प्रकारों पर विचार करते हुए कोई आयात नहीं पाया गया था। इसके अलावा, इस तरह के आयात का लगभग 20% दूसरे देश से एक विशेष प्रकार के पीयूआई द्वारा कवर किया गया था और शेष 2 प्रकार कुल आयात के 0.25% से कम थे। इस तरह की नगण्य मात्रा पर निर्भरता के परिणामस्वरूप विकृत निर्धारण हो सकता है और इसे सामान्य मूल्य के आधार के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है।
 - ग) चूंकि विश्वसनीय जानकारी के अभाव में प्रारंभिक दो विकल्पों को नहीं अपनाया जा सकता है, प्राधिकारी तीसरे विकल्प को चुनने के लिए बाध्य है जो कि समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में भुगतान या देय मूल्य है, यदि आवश्यक हो, तो उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित किया गया है।

ड.1.2. पीयूआई का निर्यात कीमत

39. जैसा कि ऊपर नोट किया गया है, पीयूआई सीकेडी/एसकेडी स्थिति में पीयूसी के आयात के अलावा और कुछ नहीं है। ऐसे परिदृश्य में पीयूआई और पीयूसी दोनों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया है। चीन जनवादी गणराज्य के किसी भी निर्यातक ने उत्तर दर्ज नहीं किया है और निर्यात कीमत की कोई जानकारी/विवरण प्रदान नहीं किया है। इसलिए प्राधिकारी ने निर्यात कीमत का निर्धारण डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकड़ों के आधार पर किया है। चीन जनवादी गणराज्य से सभी निर्यातकों के संबंध में कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमतों का निर्धारण कारखानागत स्तर पर निर्यात मूल्य का निर्धारण करने के लिए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर समुद्र भाड़ा, बीमा, कमीशन, बैंक प्रभारों, बीमा, पत्तन व्ययों और अंतर्देशीय भाड़ा प्रभारों के लिए यथोचित समायोजन करने के बाद में दी गई है। पीयूआई और पीयूसी के लिए इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात कीमत नीचे तालिका मूल्य है। सामान्य मूल्य (एनवी) जांच की अवधि के दौरान पीयूआई की औसत खरीद और खपत कीमत का किया जाता है।

40. उपरोक्त के आधार पर जांच की अवधि के लिए परिकलित पाटन मार्जिन को नीचे सारणीबद्ध किया गया है

पीयूआई	मात्रा (किग्रा.)	निवल निर्यात कीमत (रु./किग्रा.)	एनवी (रु./किग्रा.)	पाटन मार्जिन (रु./किग्रा.)	पाटन मार्जिन - % रेंज
बीम	31,048	86.75	***	***	(10)-0
ब्रेक ड्रम	1,83,845	64.61	***	***	0-10
ब्रेक शू	7,16,206	93.70	***	***	20-30
ब्रेक स्पाइडर	60,272	170.59	***	***	10-20
कैमशाफ्ट	2,83,486	99.18	***	***	20-30
हब	81,767	51.79	***	***	60-70
स्लैक समायोजक	3,35,934	89.81	***	***	10-20
भारित औसत	16,92,558	91.27	***	***	15-25

41. इसके अलावा, प्राधिकारी ने फा. संख्या 7/7/2021-डीजीटीआर, मामला संख्या एडी (एसएसआर)-7/2021 दिनांक. 19.04.2021 के तहत पीयूसी के लिए निर्णायक समीक्षा जांच आरम्भ की। चूंकि पीयूसी का निर्माण पीयूआई की एसेंबली से किया जा रहा है, जिसमें मूल्यवर्धन शामिल है, इसलिए प्राधिकारी ने पीयूसी का सीएनवी लिया है और ***% के मूल्यवर्धन को घटाकर पीयूआई के सीएनवी पर आ गया है और इसकी तुलना सामान्य मूल्य की एक वैकल्पिक विधि के रूप में पीयूआई की निवल निर्यात कीमत से की है। मूल्य नीचे सारणीबद्ध है।

एसएसआर में सीएनवी	रु./किग्रा	***
जांच अवधि के दौरान आरएम लागत के कारण वृद्धि जोड़ें @ *** %	रु./किग्रा	***
कुल लागत	रु./किग्रा	***
कम मूल्यवर्धन *** %	रु./किग्रा	***
पीयूआई के लिए सीएनवी	रु./किग्रा	***
पीयूआई के लिए एनईपी	रु./किग्रा	91.27
पाटन मार्जिन	रु./किग्रा	***
पाटन मार्जिन	% रेंज	10-15

42. यह देखा जा सकता है कि इस पद्धति के आधार पर पीओई के लिए पाटन मार्जिन डि मिनिमस से अधिक है। इस प्रकार दोनों पद्धतियों को लागू करने से यह देखा जाता है कि पीयूआई को पाटित किया जा रहा है।

च. परिवंचना और उसके प्रभावों का आकलन, यदि कोई हो:

च. 1 परिवंचना के साक्ष्य

च. 1.1 घरेलू उद्योग के विचार

43. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे:

- i. यॉर्क, आयुक्त सीमा शुल्क (आयात) न्हावा शेवा के इनपुट के आधार पर प्राधिकारी द्वारा आरम्भ की गई वर्तमान परिवंचना रोधी पहल का पूरी तरह से समर्थन करता है।
- ii. वर्तमान जांच को बैकड्रॉप में भी देखने की जरूरत है कि यॉर्क द्वारा दिनांक 12.10.2017 को परिवंचना रोधी और जांच के लिए एक आवेदन दर्ज किया गया था जिसे प्राधिकारी द्वारा दिनांक 10.04.2018 को अधिक प्रमाणों के अभाव में बंद कर दिया गया था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सम्बद्ध एडीडी से संबंधित धोखाधड़ी प्रथाएं अत्यधिक प्रचलित हो गई हैं कि सक्षम अधिकारियों ने स्वयं इस तरह की प्रथाओं पर ध्यान देना आरम्भ कर दिया है।
- iii. जांच के आरम्भ में पीयूसी और पीयूआई अच्छी तरह से परिभाषित हैं और मामले के तथ्य यह स्पष्ट करते हैं कि पीयूआई सीकेडी/एसकेडी स्थिति में पीयूसी के केवल आयात के अलावा कुछ नहीं है।
- iv. 'एक्सल फॉर ट्रेलर्स' को ट्रेलर एक्सल के हिस्से के रूप में घोषित करके 'एक्सल फॉर ट्रेलर्स' पर एडीडी से बचने के इरादे से सीकेडी (पूर्ण नॉक डाउन)/एसकेडी (सेमी नॉक डाउन) स्थिति में आयात किया जा रहा है, और कुछ आयातकों द्वारा अपनाई जा रही प्रथाएं पीयूआई की परिभाषा पूरी तरह से इसे इस तरह दर्शाती है। पीयूसी और पीयूआई की परिभाषा यह स्पष्ट करती है कि 'एक्सल फॉर ट्रेलर्स' के आयात के समय लागू पीयूआई वारंट एडीडी के आयात को पीयूआई के ऐसे आयातों तक बढ़ाया जाएगा और हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं।
- v. पीयूआई सीकेडी/एसकेडी स्थिति में पीयूसी के अलावा और कुछ नहीं है। ऐसे आयातों का विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क के अपवंचन के अलावा कोई अन्य औचित्य नहीं है। इसके बाद पीयूआई को बहुत ही न्यूनतम मूल्यवर्धन के साथ पीयूसी के रूप में असेंबल किया जाता है, यह परिवंचना बहुत स्पष्ट है।
- vi. वर्तमान मामले के तथ्य, पीयूसी से पीयूआई में एडीडी के विस्तार को वारंट करने के लिए एक परिवंचना रोधी जांच की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
- vii. नीचे दिए गए तथ्यों से पता चलता है कि वर्तमान मामला एसी नियम के तहत सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है;
 - क) पाटन रोधी जांच के बाद या उसके ठीक पहले आरम्भ या बढ़ा हुआ प्रचालन और पुर्जे और घटकों को पाटन रोधी शुल्क लगाने के उद्देश्य से अधिसूचित मूल देश या निर्यात के देश से आयात किया जाता है।
 - ख) असेंबली या कंप्लीशन ऑपरेशन के दौरान लागू इनपुट में जोड़ा गया मूल्य, निर्माण लागत के 35% से कम है।
 - ग) पीयूआई का आयात जो सीकेडी/एसकेडी स्थिति में पीयूसी के अलावा कुछ नहीं है, पाटित दरों पर बनी हुई है।
 - घ) शुल्क से बचकर पीयूआई के आयात ने पीयूसी पर लगाए गए एडीडी के उपचारात्मक प्रभाव को कम कर दिया है।
 - ड.) पीयूआई का आयात केवल लागू शुल्क से बचने के लिए था
- viii. कुछ आयातकों ने पिछली एडीडी जांच के बाद एडीडी से बचने के लिए पीयूसी के बजाय पीयूआई आयात करने की प्रथा शुरू की है जो डीजीसीआई के अनुसार पीयूसी और पीयूआई के आयात की प्रवृत्ति में स्पष्ट है।

वर्ष	पीयूसी		पीयूआई	
	मात्रा (किलो)	प्रवृत्ति	मात्रा (किलो)	प्रवृत्ति
2016-17	43,96,135	100	15,67,164	100
2017-18	34,26,319	78	36,46,430	233
2018-19	43,51,635	99	52,94,573	338
2019-20	22,27,747	51	25,58,862	163

- ix. डीजीसीआई एण्ड एस के अनुसार आयात दर्शाता है कि जबकि पीयूसी का आयात 4396135 किग्रा से घट कर 2227747 किग्रा हो गया, पीओआई का आयात 1567164 किग्रा से बढ़कर 2558862 किग्रा हो गया जो महत्वपूर्ण वृद्धि है और पीयूसी से पीओआई आयात में स्पष्ट बदलाव को इंगित करता है। पीयूआई के आयात में दिनांक 29.11.2016 को एडीडी लगाने के बाद की अवधि में बहुत उल्लेखनीय वृद्धि है।
- x. एचडी ट्रेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के आईक्यूआर के अनुसार आयात के विवरण से पता चलता है कि पीयूआई का आयात जो वर्ष 2015-16 में 12963 किग्रा था, जो कि एडीडी से पहले था, जांच की अवधि में बढ़कर 342914 किग्रा हो गया है जो अकेले पीयूसी से पीयूआई में आयात बदलाव को दर्शाता है। आयातक के अनुसार, उनके द्वारा पीयूसी का आयात इसी अवधि में शून्य रहा है।
- xi. तथ्यों से पता चलता है कि पाटन रोधी जांच के बाद या उसके ठीक पहले आरम्भ या बढ़ा हुआ संचालन और पुर्जे और घटकों को मूल देश या निर्यात के देश से आयात किया जाता है, जिसके बजाय पाटन रोधी शुल्क केवल लागू एडीडी से बचने के इरादे से पीयूसी लगाने के उद्देश्य से अधिसूचित किया जाता है।
- xii. पीयूआई के आयात के बाद पीयूसी बनाने के लिए पीयूआई पर मूल्य वर्धन ,15-20% से अधिक नहीं होगा, जो नियम जिसमें 35% की एक न्यूनतम मूल्य संवर्धन अधिदेशित है,के निर्धारित मूल्य वर्धन आवश्यकता से अधिक है। एचडी ट्रेलर जैसे प्रमुख आयातक चीन जन.गण से सभी प्रमुख भागों का आयात कर रहे हैं और उस स्थिति में मूल्यवर्धन किसी भी मामले में 35% से अधिक नहीं हो सकता है।
- xiii. एचडी ट्रेलरों ने अपने आईक्यूआर में कहा है कि उनकी "गतिविधि पीयूसी का उत्पादन करने के लिए स्थानीय सामग्री के साथ आयातित पीयूआई को इकट्ठा करना है" और यह आगे अनुरोध किया गया था कि वे एक्सल बीम/ट्यूब, कैम शाफ्ट, कैम सेट, स्लैक एडजस्टर और हब कैप आयात करते हैं। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक्सल बीम/ट्यूब में कच्चे माल की लागत और पीयूसी की समग्र लागत का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और यदि इतना बड़ा हिस्सा आयात किया जा रहा है, तो ऐसे में मूल्यवर्धन की संभावना 35% है। संयोजन व्यावहारिक रूप से लगभग असंभव है।
- xiv. यॉर्क के पास आयातकों द्वारा मूल्यवर्धन के किसी भी वास्तविक आंकड़ों तक पहुंच नहीं है। एचडी ट्रेलरों द्वारा दर्ज की गई प्रतिक्रिया पूरी तरह से दोषपूर्ण प्रतीत होती है और जब तक पक्ष सभी विवरणों के साथ अपनी प्रतिक्रिया की पुष्टि नहीं करता है, तब तक पीयूसी की लागत और पीयूआई से पीयूसी के मूल्यवर्धन विवरण के किसी भी निर्धारण की अनुमति नहीं होगी। हम प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि एचडी ट्रेलरों को पीयूसी के उत्पादन की लागत के विवरण के साथ-साथ पीयूसी के उत्पादन की लागत का निर्धारण करने के लिए आयातित और घरेलू रूप से खरीदे गए पुर्जों के पूर्ण विवरण और पीयूआई चरण से पीयूसी चरण तक कंपनी द्वारा किए गए मूल्यवर्धन को साझा करने के लिए निर्देश दें।
- xv. पीयूसी के आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को कम बनाए रखा और इस तरह की कीमत सीकेडी / एसकेडी हालत में पीयूसी के आयात को प्रभावित करती है।
- xvi. पीयूसी के आयात की बाजार हिस्सेदारी पीओआई में बहुत अधिक बनी रही क्योंकि पीयूसी के रूप में सीकेडी /एसकेडी स्थिति में अर्थात पीओआई भारत तक पहुँचता रहा। पीयूआई के आयात में वृद्धि इस तथ्य को दर्शाती है कि पीयूसी के आयात में कमी ने डीआई को अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद

नहीं की क्योंकि पीयूसी बिना किसी एडीडी के सीकेडी/एसकेडी स्थिति में भारत तक पहुंचना जारी रहा। इस प्रकार, घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा प्रभावित हुआ।

- xvii. एक सीकेडी / एसकेडी हालत में पीयूसी के आयात के परिणाम के रूप में, घरेलू उद्योग की बिक्री, उत्पादन और क्षमता उपयोग एक बार फिर से वर्ष 2016-17 और 2018-19 के बीच कुछ सुधार के बाद पीओआई के दौरान गिरावट आई।
- xviii. यहां तक कि घरेलू उद्योग के कीमत मानदंड भी पीयूआई के आयातों द्वारा निर्मित प्रतिकूल स्थिति को दर्शाते हैं। डीआई की लाभप्रदता जो 2016-17 की अवधि में नकारात्मक स्तर से 2017-18 में सकारात्मक हो गई है, एक बार फिर पीओआई में नकारात्मक हो गई है।
- xix. आरओसीई का भी मामला इसी प्रकार है। आरओसीई जिसमें 2016-17 और 2018-19 के बीच सुधार हुआ है, पीओआई में नगण्य स्तर तक गिर गया और 0-5% की सीमा में था।
- xx. डीआई की समग्र स्थिति पीओआई में वास्तविक क्षति को दर्शाती है और ऐसी क्षति का कारण सीकेडी/एसकेडी स्थिति में पीयूसी का आयात है और पीयूसी पर लागू शुल्कों को पीयूआई को भी विस्तारित करके स्थिति को ठीक किया जा सकता है जो कि पीयूसी के सीकेडी/एसकेडी की स्थिति के अलावा और कुछ नहीं है।
- xxi. एचडी ट्रेलर्स ने तर्क दिया था कि उन्हें सूचित किया जाना चाहिए कि यॉर्क ने राजस्व खुफिया विभाग (डीआरआई) से धोखाधड़ी प्रथाओं से संबंधित एक पत्र कैसे प्राप्त किया। कंपनी का इरादा आरोप निराधार है और प्रस्तुत पत्र से पता चलता है कि पत्र सामान्य क्रम में ही रहा है।
- xxii. सीमा शुल्क आयुक्त की कार्रवाइयों पर एचडी ट्रेलर्स की दलीलें कोई दम नहीं हैं। सीमा शुल्क आयुक्त ने सही ढंग से धोखाधड़ी पर संदेह किया और इसके विपरीत दावे स्वयं सेवा कर रहे हैं।
- xxiii. एचडी ट्रेलर्स द्वारा उठाए गए सीमा शुल्क आयुक्त से पत्र की प्रतिलिपि के अनुरोध की कोई कानूनी वैधता नहीं है। नियम 26 यह दर्शाता है कि प्राधिकारी *स्वप्रेरणा से जांच* आरम्भ करने का आधार बनने वाले व्यौरों को हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा करने के लिए बाध्य नहीं है और केवल यह है कि पक्षकारों को जांच आरम्भ करने पर नियम 6 के अनुसार सूचना प्रदान करने की अनुमति दी जा सकती है। इस प्रकार, प्राधिकारी सीमा शुल्क आयुक्त से प्राप्त जानकारी को पार्टियों के साथ साझा करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है।
- xxiv. एचडी ट्रेलर्स के लिए यह कहने का कोई आधार नहीं है कि यॉर्क द्वारा प्रस्तुत डीआरआई पत्र अन्य पक्षों को दिया जाए या रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। पत्र उचित माध्यम से प्राप्त किया गया था और इसे रिकॉर्ड के भाग के रूप में माना जाना चाहिए। एचडी ट्रेलर्स शुल्कों से बचने की अनेक प्रक्रियाओं में संलग्न एक कम्पनी है और वे किसी कानून के समझ के बिना उसकी अपने पक्ष में व्याख्या करके स्कॉट मुक्त नहीं हो सकते हैं।
- xxv. एचडी ट्रेलर्स का अनुरोध कि 1.1.2018 से पहले डीजीसीआईएंडएस डेटा के लिए अनुमति नहीं दी गई है, केवल एक बहाना है, जैसा कि ज्ञात होता है। यदि वे डीजीसीआईएंडएस आंकड़े प्राप्त करने के सम्बंध में गंभीर हैं, कंपनी ने किसी भी अवधि के लिए कोई विश्लेषण एकत्र और प्रस्तुत नहीं किया है।
- xxvi. यह तर्क कि पाटन और क्षति की आवश्यकता को पूरा नहीं किया गया है, एचडी ट्रेलर्स द्वारा बिना किसी आधार के दिया गया एक बयान है। पाटन और क्षति परिवर्चना मामले में सम विषयक नहीं है और एक नए मामले तथा परिवर्चना पूरी तरह से भिन्न है।
- xxvii. एचडी ट्रेलर्स द्वारा दिया गया यह निराधार बयान है कि यॉर्क ने चीन जन.गण से आयात किया है। यह अनुरोध किया गया है कि कंपनी या उसके संबंधित पक्ष ने चीन जन.गण से आयात नहीं किया या चीन जन.गण में उसके किसी भी संबंधित पक्ष ने भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात नहीं किया।
- xxviii. पीओआई के मूल्य निर्धारण पर यॉर्क का दावा सही नहीं है और बिना किसी आधार का है। शुल्क से बचने के लिए पीयूसी को पीयूआई के रूप में आयात किया जाता है।
- xxix. यह तर्क कि सामग्री प्रबंधन और वित्तीय पहलुओं से संबंधित यॉर्क के आंकड़े एक दूसरे के विरोधाभासी हैं और फॉरेंसिक ऑडिट की आवश्यकता है, एक निराधार तर्क है। लेखापरीक्षित वित्तीय रिपोर्ट नियम के

अनुसार प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के लिए उत्तरदायी हैं और यॉर्क को इस तरह के किसी भी सत्यापन पर कोई आपत्ति नहीं है।

च. 1.2. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों के विचार

44. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नानुसार अनुरोध किए हैं:

- i. एचडी ट्रेलर्स प्राइवेट लिमिटेड ने अनुरोध किया है कि उनकी गतिविधि पीयूसी का उत्पादन करने के लिए स्थानीय सामग्री के साथ आयातित पीयूआई को एकत्र करना है।
- ii. मेसर्स एचडी ट्रेलर्स प्रा. लिमिटेड ने ट्रेलर एक्सल पर एडीडी अधिरोपित करने से बहुत पहले ट्रेलर एक्सल के निर्माण के लिए अपनी फैक्ट्री स्थापित की है और अब ट्रेलर एक्सल के लगभग 70% घटक स्वदेशी हैं।
- iii. एचडी ट्रेलर ड्रम, ब्रेक शू असेंबली आदि जैसे सभी भागों का आयात नहीं कर रहे हैं।
- iv. एचडी ट्रेलर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत लागत शीट में 69% से अधिक का मूल्यवर्धन दिखाया जाएगा जो कि नियम में प्रदान की गई 35% की सीमा से बहुत अधिक है।
- v. असेम्बल्ड, पूर्ण और तैयार सामाग्रियों की लागत से आयातित कच्चे माल की लागत को घटाकर मूल्य वर्धन प्राप्त करना है।
- vi. एक्सल बीम ट्यूब एक्सल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। बाकी निर्माताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली ट्यूब में वेलडिंग से जुड़े एक से अधिक भाग होते हैं। आयातित ट्यूब सीमलेस है और इस प्रकार अधिक शक्तिशाली है। कोई भी भारतीय उत्पादक सीमलेस का निर्माण नहीं करता है। इसी तरह आयातित हब कैप एक बेहतर उत्पाद है।
- vii. एचडी ट्रेलर्स प्रा. लिमिटेड को घरेलू उत्पादक के रूप में माना जाना चाहिए न कि आयातक के रूप में क्योंकि मूल्यवर्धन 69% से अधिक है।
- viii. एचडी ट्रेलर प्रा. लिमिटेड ने दिनांक 01.04.2015 से अब तक डीजीसीआईएंडएस से आयात आंकड़ों तक पहुंचने की अनुमति के लिए अनुरोध किया है। डीजीसीआईएंडएस के पास केवल सितंबर 2020 तक का उक्त आंकड़े उपलब्ध है किंतु डीजीटीआर ने उक्त कंपनी को केवल जनवरी 2018 से आंकड़ों आयात करने की अनुमति दी है। अतः, मेसर्स एचडी ट्रेलर्स प्रा. लिमिटेड आवश्यक आंकड़ों के उस हिस्से तक नहीं पहुंच सका जिसकी उसे आवश्यकता थी।
- ix. डीजीटीआर की दिनांक 15.09.2020 की जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना जांच के लिए आधार के रूप में सीमा शुल्क आयुक्त(आयात), न्हावा शेवा से प्राप्त सूचना के संदर्भ में है। उक्त पत्र की एक प्रति उपलब्ध कराने के कंपनी के अनुरोध का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।
- x. मेसर्स एचडी ट्रेलर्स प्रा. लिमिटेड ने दावा किया है कि यॉर्क की पहुँच डीआरआई के पत्र तक थी। तथापि, इस संबंध में डीजीटीआर से उसका अनुरोध, उत्तर प्राप्त करने में विफल रहा।
- xi. जांच आरम्भ करने के लिए दो प्रमुख आवश्यकताएं हैं पाटन और क्षति, जो वर्तमान मामले में पूरी नहीं हुई है जैसा कि यॉर्क के निवेदनों से देखा जा सकता है।
- xii. सीमा शुल्क आयुक्त, न्हावा शेवा के पत्र के संदर्भ में, यदि उन्होंने इस मुद्दे का सही परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण किया होता, वे स्वयं पता लगा सकते थे कि मेसर्स एचडी ट्रेलर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयात एक्सल की लागत का केवल 31% है और इस प्रकार से परिवंचना का कोई सवाल ही नहीं है। यदि इन तथ्यों पर विचार किया गया होता, तो स्थिति के परिणामस्वरूप वर्तमान जांच आरम्भ नहीं होती।
- xiii. सीमा शुल्क आयुक्त, न्हावा शेवा को यह महसूस करना चाहिए था कि एचडी ट्रेलर्स प्राइवेट लिमिटेड धोखा नहीं दे रहा है, लेकिन आयात परिधि मानदंड पर विचार करने के लिए निर्धारित सीमा से काफी आगे है।
- xiv. मेसर्स एचडी ट्रेलर्स प्रा लिमिटेड का सीमा शुल्क आयुक्त, न्हावा शेवा को आपूर्ति के लिए अनुरोध पत्र को स्वीकार नहीं किया गया है। अतः, कंपनी जांच आरम्भ करने के औचित्य के साथ-साथ एक प्रभावी अभ्यावेदन करने से वंचित है।

- xv. या तो डीआरआई का पत्र मेसर्स एचडी ट्रेलर्स प्राइवेट लिमिटेड को प्रस्तुत किया जाना चाहिए था या इसे जांच में विचार की जाने वाली सामग्री से हटा दिया जाना चाहिए।
- xvi. दिनांक 1.4.2015 से आयात आंकड़ों की आपूर्ति के लिए कंपनी के अनुरोध को छोटा कर दिया गया है और केवल दिनांक 1.1.2018 से आंकड़ों की अनुमति दी गई थी। इस प्रकार, इसे प्रासंगिक अवधियों के लिए आयात आंकड़ों का विश्लेषण करने से रोका गया था।
- xvii. मेसर्स यॉर्क ने गलत अनुरोध किया है। यॉर्क ने प्रासंगिक अवधि के दौरान चीन जन.गण से आयात किया है और इसे डीजीसीआईएंडएस से आंकड़े प्राप्त करके सत्यापित किया जा सकता है।
- xviii. मेसर्स यॉर्क की पीओआई के मूल्य निर्धारण के सम्बंध में अनुरोध गलत हैं और किसी भी सबूत द्वारा समर्थित नहीं हैं। कम से कम वे अपने संदेहों को स्थापित करने के लिए अपनी लागत आंकड़े प्रस्तुत कर सकते थे।
- xix. मटेरियल हैंडलिंग और वित्तीय पहलुओं के सम्बंध यॉर्क के आंकड़े एक-दूसरे के विरोधाभासी हैं। इस प्रकार, एक फॉरेंसिक लेखा परीक्षा यह पता लगाने के लिए आवश्यक है कि उनकी घोषणाएं सही हैं या नहीं।
- xx. एचडी ट्रेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के पास घरेलू स्तर पर 69% हिस्से थे इसलिए कंपनी को डीआई के रूप में माना जाना चाहिए। कोई भी भारतीय उत्पादक सीमलेस ट्यूब नहीं बनाता है इसलिए इसे आयात किया जाता है।

च. 2 प्राधिकारी द्वारा जांच

45. प्राधिकारी विभिन्न हितबद्ध पक्षों द्वारा किए गए निवेदनों और अधिनियम/नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों को निम्नानुसार नोट करता है :

सीमा प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9क(1क),

जिसमें केंद्र सरकार, ऐसी जांच, जिसे वह आवश्यक समझे, का यह मत है कि उप धारा (1) के तहत लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना हुई है, या तो विवरण अथवा नाम अथवा उस वस्तु के संगठन में परिवर्तन करके, जो ऐसे पाटनरोधी शुल्क के अध्यक्षीन है अथवा ऐसी वस्तु का आयात अनअसेंबलड अथवा डिसअसेंबलड रूप अथवा उसके मूल देश को बदलकर अथवा निर्यात अथवा किसी अन्य तरीके से किया गया है जिसमें लगाया गया पाटनरोधी शुल्क अप्रभावी रखा गया है, वह ऐसी वस्तु अथवा उस देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क लगा सकती है, जैसी भी स्थिति हो।

पाटनरोधी नियमावली का नियम 25:

II. "25. पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना – (1) प्रवंचना पर किसी परिपाटी, प्रक्रिया अथवा कार्य, जिसके लिए शुल्क लगाए जाने को छोड़कर अपर्याप्त कारण अथवा आर्थिक औचित्य है, के परिणामस्वरूप भारत और उपायों के अध्यक्षीन किसी देश में अलग-अलग कंपनियों के बीच अथवा किसी देश और भारत के बीच व्यापार के पैटर्न में परिवर्तन के रूप में विचार किया जाएगा; और जहां क्षति का साक्ष्य है अथवा शुल्क के उपचारात्मक प्रभाव कीमतों अथवा गुणवत्ताओं अथवा समान उत्पाद के दोनों के संदर्भ में कम किए जा रहे हैं, और जहां समान उत्पाद के लिए पूर्व में सिद्ध सामान्य मूल्यों के संबंध में पाटन का साक्ष्य है, यदि उपयुक्त परिवर्तनों अथवा समायोजनों अथवा नियम 10 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक हो।"

(2) उप नियम (1) में उल्लिखित परिपाटी, प्रक्रिया अथवा कार्य में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) जहां पाटनरोधी शुल्क के अध्यक्षीन किसी वस्तु का पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के प्रयोजन के लिए अधिसूचित निर्यातक देश अथवा मूल देश सहित किसी भी देश से भारत में अनअसेंबलड, अनफिनिशड अथवा इनकम्प्लीट रूप में किया जाता है तथा उसे भारत में अथवा ऐसे देश में असेंबल, फिनिशड अथवा कम्प्लीट किया जाता है तो ऐसी असेंबलिंग, फिनिशिंग अथवा कम्प्लीशन को लागू पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना माना जाएगा, यदि:

(i) प्रचालन पाटनरोधी जांच के बाद अथवा ठीक उससे पूर्व प्रारंभ किया गया हो अथवा बढ़ाया गया हो तथा हिस्से पुर्जों एवं संघटकों का पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के प्रयोजन के लिए अधिसूचित मूल देश अथवा निर्यातक देश से आयात किया गया हो;

और

(ii) असेंबलिंग, फिनिशिंग अथवा कम्प्लीशन के कार्य के परिणामस्वरूप मूल्य असेंबलड, फिनिशड अथवा कम्प्लीट वस्तु की लागत के 35 प्रतिशत से कम हो।

बशर्ते कि प्रौद्योगिकी की खरीद, यथा पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, रॉयल्टी, तकनीकी जानकारी, परामर्शी प्रभार आदि के निमित्त मूल्यवर्धन व्यय के परिकलन में उल्लिखित हिस्से-पुर्जों के मूल्य में शामिल नहीं किया जाएगा।

व्याख्या-I – मूल्य का अर्थ असेंबलड, फिनिशड अथवा कम्प्लीट वस्तु की लागत में से आयातित हिस्सों पुर्जों अथवा संघटकों का मूल्य घटाकर

व्याख्या-II – “मूल्य” का परिकलन करने के प्रयोजन के लिए बौद्धिक संपत्ति अधिकार, रॉयल्टी, तकनीकी जानकारी शुल्क तथा परामर्शी प्रभारों से संबंधित भुगतानों के निमित्त किए गए खर्चों को हिसाब में नहीं दिया जाएगा।

(ख) जहां पाटनरोधी शुल्क के अध्यक्षीन कोई वस्तु मूल देश से अथवा वस्तु के विवरण, नाम अथवा निर्माण के परिवर्तन में शामिल किसी प्रक्रिया के अध्यक्षीन रखे जाने के बाद पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के लिए अधिसूचित निर्यात के देश से भारत में आयात किए जाते हैं, वहां ऐसे परिवर्तन लागू पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना के लिए माने जाएंगे, यदि पाटनरोधी शुल्क के अध्यक्षीन उस वस्तु के विवरण अथवा नाम अथवा निर्माण के परिवर्तन के फलस्वरूप प्रशुल्क वर्गीकरण, यदि कोई है, के अंतर को ध्यान में रखते हुए छोटे रूपों में भी दिखाई देने वाले अथवा उस स्वरूप में वस्तु में परिवर्तन हो रहा है।

(ग) जहां पाटनरोधी शुल्क के अध्यक्षीन कोई वस्तु उस निर्यातक अथवा उत्पादक अथवा देश के माध्यम से भारत में आयातित की जाती है जो पाटनरोधी शुल्क के अध्यक्षीन नहीं है तो ऐसे निर्यात लागू पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना के लिए माने जाएंगे, यदि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के लिए अधिसूचित निर्यातक अथवा उत्पादक उस वस्तु की अपनी व्यापार परिपाटी, व्यापार पैटर्न अथवा बिक्री के चैनल में निर्यातकों अथवा उत्पादकों अथवा उस देश के माध्यम से भारत में निर्यातित अपने उत्पादों को देने के लिए परिवर्तन करते हैं जो पाटनरोधी शुल्क के अध्यक्षीन नहीं हैं।

(घ) अन्य कोई तरीका जिससे इस प्रकार लगाया गया पाटनरोधी शुल्क अप्रभावी किया गया है।

46. प्राधिकारी ने पीयूसी और पीयूआई दोनों के आयातों की जांच के प्रयोजन के लिए, डीजीसीआईएंडएस द्वारा उपलब्ध कराए गए लेनदेन-वार आयात आंकड़ों पर विचार किया है। पीयूआई के रूप में सीकेडी/एसकेडी की स्थिति में पीयूसी का आयात करके पीयूसी पर लगाए गए शुल्कों की हेराफेरी के आरोप के संबंध में, प्राधिकारी ने इस जांच में विशेष रूप से परिवंचना के उक्त रूप की जांच की है।
47. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादकों/निर्यातकों अथवा निर्यातकों ने इस मामले में कोई प्रश्नावली उत्तर दर्ज नहीं किया है। प्राधिकारी आगे यह भी नोट करते हैं कि एडी उपाय उत्पादक/निर्यातक विशिष्ट है और एक एडी जांच के अधीन उत्पादकों/निर्यातकों को आंकड़े प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि विशेष रूप से उनके द्वारा एक उपाय की वसूली के बाद व्यापार पैटर्न में बदलाव किया जा सके। साथ ही, पीयूआई को पीयूसी में बदलने से संबंधित मूल्यवर्धन की भी गणना की जाती है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन.गण से कोई भी उत्पादक/निर्यातक ने वर्तमान जांच में प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जैसा कि पूर्वगामी पैरा में उल्लेख किया है।
48. हितबद्ध पक्षों का दावा को वर्तमान जांच में सुसंगत भाग में तथ्य: का समाधान किया गया है और इसलिए अलग से इसका समाधान नहीं किया जा रहा है। तथापि, एचडी ट्रेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के विवाद के संबंध में कि सीमा शुल्क आयुक्त, न्हावा शेवा से प्राप्त जानकारी, जो वर्तमान जांच का आधार है, को उन लोगों के साथ साझा नहीं किया गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं पाटन रोधी नियम के तहत जांच आरम्भ करने वाले प्राधिकारी का दायित्व हितबद्ध पक्षों को आवश्यक जानकारी प्रदान करें जिससे कि उन्हें अपने निवेदन के लिए एक निष्पक्ष और उचित अवसर मिल सके और उनके हितों की रक्षा करने कर सके तथा जांच आरम्भ करने के नोटिस द्वारा विधिवत संज्ञान लिया गया है जो वर्तमान जांच का आधार बनाने विशिष्ट विवरण निहित है और सभी हितबद्ध पक्षों को नियम के तहत आवश्यक अपने विचार और साक्ष्य प्रदान करने का अवसर दिया गया था। यह एचडी ट्रेलर्स द्वारा तर्क दिया गया है कि मामले पाटन और क्षति की शर्तों को को पूरा नहीं करते। तथापि, यह नोट किया

गया है कि इस तरह की कोई आवश्यकता परिवर्चना रोधी जांच का भाग नहीं है। इसके अलावा, यह भी पाया गया है कि मेसर्स एच डी ट्रेलर्स को वर्तमान मामले के निष्कर्ष पर विशेष विचार करते हुए पीओआई के आयातों के बेहतर प्रशंसा के लिए डीजीसीआई एण्ड एस डेटा की खरीद करने के लिए आवश्यक अनुमति प्रदान किया गया है।

49. इसके अलावा, भारत में पीयूआई के आयातकों में से एक, एचडी ट्रेलर्स प्राइवेट लिमिटेड ने कुछ जानकारी दर्ज की है और यह नोट किया गया है कि कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी में काफी कमी है और तैयार माल की लागत और पीयूआई से पीयूसी चरण में मूल्यवर्धन निर्धारित करने के लिए इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।
50. उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों से सहयोग की अनुपस्थिति को देखते हुए, प्राधिकारी ने सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर पीयूआई को पीयूसी में परिवर्तित करने में ट्रेड पैटर्न शिफ्ट और मूल्यवर्धन पर विचार किया। जबकि डीजीसीआई एण्ड एस से प्राप्त आयात डाटा को व्यापार पैटर्न शिफ्ट के लिए उपयोग किया गया है, वहीं, सम्बद्ध वस्तुओं के सहयोगी घरेलू निर्माता द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का उपयोग पीयूसी को पीओआई से मूल्य संवर्धन सहित प्रयोजनों के लिए किया गया है। प्राधिकारी व्यापार पैटर्न, पीयूसी से पीओआई का अतिरिक्त नया मूल्य संवर्धन पर निर्धारित मापदंड की जांच की चाहे व्यापार पैटर्न में परिवर्तन आर्थिक औचित्य के कारण हो अथवा वसूली नियम के 25(1) अनुसार एडीडी की वसूली को प्रभावित करने के लिए परिवर्चना के कारण हो।

च. 2.1 व्यापार के पैटर्न में परिवर्तन

51. प्राधिकारी ने पीयूसी से पीयूआई में व्यापार पैटर्न में बदलाव पर निर्धारित मानदंडों की जांच की है, चाहे व्यापार पैटर्न में परिवर्तन एक आर्थिक औचित्य के कारण है या नियम 25(1)के अनुसार एडीडी की वसूली को प्रभावित करने के लिए धोखाधड़ी के कारण है।
52. व्यापार की पद्धति में बदलाव का विश्लेषण पीओआई और पीयूसी के आयात के मात्रा का विश्लेषण करके 2016-17 से पीओआई तक का किया गया है। डीजीसीआईएण्डएस आंकड़ों के अनुसार पीयूसी और पीयूआई के आयात की प्रवृत्ति को निम्नानुसार नोट किया गया है:

वर्ष	पीयूसी		पीयूआई	
	मात्रा (एमटी)	प्रवृत्ति	मात्रा (एमटी)	प्रवृत्ति
2016-17	4,396	100	1,527	100
2017-18	3,426	78	3,513	230
2018-19	4,352	99	5,007	328
2019-20	2,228	51	1,779	117

53. यह नोट किया गया है कि चीन जन.गण से पीयूसी का आयात आधार वर्ष में 4396 एमटी से घट कर पीओआई द्वारा 2228 एमटी हो गया जबकि पीयूआई का आयात जो आधार वर्ष में 1527 एमटी था, पीओआई में बढ़कर 1779 एमटी हो गया, जो कि, जांच की अवधि अर्थात तत्काल पिछले वर्ष के दौरान पीयूआई के आयातों में गिरावट आने के बाद भी पर्याप्त वृद्धि है।
54. इस प्रकार, यह नोट किया गया है कि पाटन रोधी शुल्क की लेवी पश्चात चीन जन. गण से पीयूसी के व्यापार पैटर्न में परिवर्तन है।

च. 2.2 व्यापार पैटर्न में बदलाव

55. डीजीसीआईएण्डएस द्वारा उपलब्ध कराए गए लेनदेन-वार आयात आंकड़ों के आधार पर पीयूसी और पीयूआई के आयात पर विचार किया गया है। पीयूसी और पीयूआई से संबंधित आयात आंकड़ों से यह बहुत स्पष्ट है कि पीयूआई का आयात पीयूसी पर एडीडी लगाने के बाद आरम्भ हुआ या बढ़ा। वर्तमान मामले में, पीयूसी पर एडीडी 2016 से प्रभावी है और पीयूआई का आयात आरम्भ हुआ या उसके बाद व्यापार पैटर्न में बदलाव की पुष्टि हुई। पीयूआई के आयात में वृद्धि के साथ, पीयूसी के आयात में गिरावट आई है।

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

चीन से आयात - पीयूसी (एमटी)	4,917	4,433	3,066	6,600	6,300	4,371	3,426	4,352	2,228
चीन से आयात - पीयूआई (एमटी)	-	-	-	-	-	1,527	3,513	5,007	1,779
कुल आयात पीयूसी और पीयूआई-एमटी	4,917	4,433	3,066	6,600	6,300	5,898	6,939	9,358	4,007
आयात पीयूसी%	100	100	100	100	100	74	49	46	56
आयात पीयूआई%	-	-	-	-	-	26	51	54	44
भारत में मांग- एमटी	16,902	13,923	8,785	16,684	24,375	28,735	42,832	40,191	15,418
घरेलू उद्योग की बिक्री-एमटी	***	***	***	***	***	***	***	***	***
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री-एमटी	***	***	***	***	***	***	***	***	***
भारतीय उत्पादकों की बिक्री-एमटी	***	***	***	***	***	***	***	***	***
भारतीय उत्पादकों का बाजार हिस्सा -%	***	***	***	***	***	***	***	***	***
डीआई का मार्केट शेयर-%	***	***	***	***	***	***	***	***	***

56. यह देखा गया है कि 2015-16 तक केवल पीयूसी के आयात हो रहे थे और नवम्बर, 2016 में एडीडी लगाने के बाद उसमें कमी आती गई। इसी तरह, पीओआई के आयात जो कि आरम्भ में 2015-16 तक शून्य था और जो पीयूसी पर एडीडी लगाने के बाद वृद्धि होने लगी है। परिणामस्वरूप, समग्र रूप से भारतीय उत्पादकों के बाजार हिस्से में वृद्धि हो रही थी और वर्ष 2016-17 में एडीडी के अधिरोपित होने के पश्चात 98.76% स्तर पर पहुंच गया था, पीओआई के आयात के प्रारंभ के बाद एक बार फिर उसमें गिरावट आने लगी और इसके परिणामस्वरूप पीओआई के दौरान भारतीय उत्पादकों के मार्केट शेयर में 74.01% के स्तर तक गिरावट आई।

च. 2.3 औचित्य, आर्थिक या अन्यथा, पाटन रोधी शुल्क अधिरोपित करने के अलावा

57. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन.गण से किसी भी उत्पादक / निर्यातक ने वर्तमान जांच में प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है और भाग लेने वाले आयातक भी पीयूसी से पीयूआई में ट्रेड पैटर्न में बदलाव को सही ठहराने के लिए पाटन रोधी शुल्क के अधिरोपण के अलावा किसी भी औचित्य, आर्थिक या अन्यथा को स्थापित करने के लिए उचित जानकारी प्रदान करने में विफल रहे।

58. आयातकों में से एक एचडी ट्रेलर्स प्राइवेट लिमिटेड की प्रतिक्रिया से यह भी नोट किया गया है कि वे एक व्यावसायिक गतिविधि के रूप में ट्रेलरों के लिए एक्सल के कुछ हिस्सों का आयात करते हैं और पार्टी ने तर्क दिया कि संबद्ध वस्तुओं के आईआर उत्पादन के अधिकांश हिस्से में अब घरेलू रूप से उत्पादित हिस्से शामिल हैं। जैसा कि नोट किया गया है, वर्तमान मामले में पीयूआई सीकेडी/एसकेडी स्थिति में पीयूसी है। पीयूआई को आयात के बाद पीयूसी में असेंबल किया जाता है और इस प्रक्रिया में लागू एडीडी स्पष्ट रूप से चोरी हो जाता है। यह रिकॉर्ड के सम्बंध में जानकारी से देखा गया है कि पीओआई, जो ट्राई के लिए धुरी का हिस्सा है एल सीकेडी/एसकेडी

हालत में ईआरएस, जैसे कोई स्वतंत्र अनुप्रयोग है और केवल पीयूसी के उत्पादन में उपयोगिता है। इसलिए, यह देखा गया है कि पीयूआई का पीयूसी में संयोजन कोई महत्वपूर्ण उत्पादन गतिविधि नहीं है और यह नोट किया जाता है कि पीयूआई को पीयूसी में असेंबल करने के लिए की गई उत्पादन गतिविधि न्यूनतम और वृद्धिशील है और एडी नियमों के नियम 25 के तहत निर्धारित मूल्यवर्धन से कम है।

59. घरेलू उद्योग ने सकल निवेश, पीओआई का पीयूसी मूल्य संवर्द्धन, रोजगार, बिक्री मूल्य और कच्चे माल की लागत पर जानकारी प्रदान की है। उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, यह देखा गया है कि संयंत्र और उपकरण, उत्पादन प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी और विनिर्माण गतिविधियां पीयूसी के उत्पादन में मुख्य रूप से शामिल हैं और पीयूसी को पीयूआई में परिवर्तित करने के कार्य में ऐसी कोई प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है।

च.2.4 मूल्य संवर्धन

60. एडी नियमों के नियम 25 की आवश्यकता है कि "असेंबली या समापन ऑपरेशन के दौरान लाए गए इनपुट में जोड़ा गया मूल्य, निर्माण लागत के 35% से कम है"। चूंकि, निर्यातकों/आयातकों से कोई सार्थक सहयोग नहीं मिल रहा है, इसलिए मूल्यवर्धन का निर्धारण सर्वोत्तम उपलब्ध जानकारी के आधार पर किया गया है।
61. मेसर्स एच.डी. ट्रेलर प्रा. लिमिटेड पी ने वर्तमान जांच में भाग लिया और आयातकों की प्रश्नावली का उत्तर दर्ज किया। उन्होंने दावा किया कि वे भारत में 69% मूल्यवर्धन करते हैं, तथापि इस तर्क को प्रमाणित करने के लिए उनके द्वारा कोई डेटा/दस्तावेज दर्ज नहीं किया गया था। प्राधिकारी ने दिनांक 17 जून, 2021 के पत्र के तहत आयातकों को समर्थित दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में एक लागत शीट दर्ज करने के लिए किया। आयातक ने अपने मेल द्वारा उसे दिनांक 29 जून, 2021 को दर्ज किया। उसकी जांच करने पर यह पाया गया कि उनके द्वारा प्रस्तुत की किए गए डेटा, वर्ष 2019-20 के लिए लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ मेल नहीं खाते, जैसा कि उनके द्वारा अनुरोध किया गया था। अतः, प्राधिकारी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और आयातक की लेखा परीक्षित वार्षिक रिपोर्ट का उपयोग करते हुए मूल्यवर्धन का निर्माण करने के लिए बाध्य थे। उसी के आधार पर मूल्यवर्धन को नीचे सारणीबद्ध किया गया है।

विवरण	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
उपभोग किए गए कच्चे माल की लागत	लाख रुपये	***	***	***	***
कुल लागत	लाख रुपये	***	***	***	***
कम आरएम लागत	लाख रुपये	***	***	***	***
व्यापारिक वस्तुओं की कम खरीद	लाख रुपये	***	***	***	***
स्टॉक में कम बदलाव	लाख रुपये	***	***	***	***
मूल्य संवर्धन	लाख रुपये	***	***	***	***
समर्पित विनिर्माण व्यय		***	***	***	***
मूल्यह्रास	लाख रुपये	***	***	***	***
अन्य प्रत्यक्ष व्यय	लाख रुपये	***	***	***	***
मरम्मत एवं रखरखाव	लाख रुपये	***	***	***	***
विनिर्माण के लिए कुल समर्पित व्यय	लाख रुपये	***	***	***	***
सामान्य व्यय	लाख रुपये	***	***	***	***
निर्माण के लिए सामान्य निर्यात का हिस्सा।	लाख रुपये	***	***	***	***
विनिर्माण के लिए मूल्यवर्धन	लाख रुपये	***	***	***	***
मूल्य संवर्धन %	% रेंज	15-25	10-20	10-20	15-25

62. यह है देखा कि विचाराधीन वर्ष से किसी वर्ष में भी, मूल्य संवर्धन की तुलना में अधिक 25% कर दिया गया है।

63. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीयूआई के रूप में पीयूसी का आयात करके पीयूसी पर लागू एडीडी चोरी करने के उद्देश्य से व्यापार के पैटर्न में बदलाव किया जा रहा है।

छ. मौजूदा पाटन रोधी उपायों और घरेलू उद्योग पर परिधि के प्रभाव का आकलन।

64. परिवर्चना किए गए उत्पाद के तरीके और उस सीमा तक, जहां अधिरोपित शुल्क को कम कर रहे हैं और ऐसे अतिरिक्त शुल्क प्रदान कर रहे हैं जो प्रतिपादन विश्लेषण किये जाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या संबद्ध देश से पीयूआई के बड़े हुए आयातों द्वारा व्यापार में बदलाव के प्रभाव के कारण बाजार हिस्सेदारी, कीमत प्रभाव और प्रमुख आर्थिक मानकों पर प्रतिकूल प्रभावों के संदर्भ में पाटनरोधी शुल्कों के उपचारात्मक प्रभावों को कम किया गया है।

छ.1 मार्केट शेयर का आकलन और घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर परिवर्चना के प्रभाव

65. प्राधिकारी ने भारतीय मांग में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से और विचाराधीन उत्पाद के आयात की जांच की है और पीयूआई के आयातों को ध्यान में रखते हुए इसे देखा है:

मांग में मार्केट शेयर	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई
घरेलू उद्योग की बिक्री	मीट्रिक टन	***	***	***	***
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	मीट्रिक टन	***	***	***	***
सम्बद्ध देश से आयात-पीयूसी	मीट्रिक टन	4,396	3,426	4,325	2,228
सम्बद्ध देश से आयात-पीयूआई	मीट्रिक टन	1,527	3,513	5,007	1,779
मांग	मीट्रिक टन	28,735	42,832	40,191	15,418
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	149	140	54
घरेलू उद्योग की बिक्री	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	140	177
अन्य भारतीय उत्पादक	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	९७	62	26
सम्बद्ध देश से आयात-पीयूसी	%	15.30	8.00	10.76	14.45
प्रवृत्ति	%	100	52	70	94
सम्बद्ध देश से आयात-पीयूआई	मीट्रिक टन	5.31	8.20	12.46	11.54
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	154	234	217

66. यह नोट किया गया कि मांग जैसा निर्धारित होता है, में पीयूसी और पीयूआई के आयात की मात्रा दोनों शामिल है। आगे यह भी नोट किया गया है कि जांच की अवधि में घरेलू उद्योग और चीन जन.गण दोनों के मार्केट शेयर में वृद्धि हुई है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, पीयूआई का उपयोग केवल पीयूसी के उत्पादन में किया जाता

है और इसकी कोई अलग उपयोग नहीं होता है। उपरोक्त सारणी से नोट किया गया कि पीयूसी का हिस्सा समान स्तर पर बना रहा, पीयूआई की आयात की हिस्सेदारी क्षति की अवधि में बढ़ती गई जो घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में और अधिक वृद्धि को रोका दिया।

छ.2 पीओआई के दौरान डीआई की निवल बिक्री वसूली पर परिवर्चना का प्रभाव

67. कीमतों पर पीयूआई के आयात के प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में परिवर्चना वाले आयातों द्वारा कीमतों में महत्वपूर्ण कटौती की गई है। प्राधिकारी नीचे दिए गए पर विचार करते हैं।

कीमत में कटौती	इकाई	2016-17	2017-18	2018-19	पीओआई
पीयूसी की आयात मात्रा	मीट्रिक टन	4,396	3,426	4,352	2,228
पीयूसी की आयात मात्रा	मीट्रिक टन	1567.16	3646.43	5294.57	2558.86
पीयूसी के आयातों का पहुंच मूल्य	रुपये/किग्रा	109.46	113.09	126.01	121.28
निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर)	रुपये/किग्रा	***	***	***	***
कीमत में कटौती	रुपये/किग्रा	***	***	***	***
कीमत में कटौती	%	***	***	***	***
कीमत में कटौती	% श्रेणी	20-30	10-20	0- 5	5- 15

68. चूंकि पीयूआई के आयातों की पहुंच कीमत की तुलना संबद्ध वस्तुओं के एनएसआर से सीधे नहीं की जा सकती है, इसलिए पीयूसी की पहुंच कीमत की तुलना संबद्ध वस्तु के एनएसआर से की जाती है। यह देखा गया है कि पीयूसी के आयात पूरे क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के एनएसआर में कटौती कर रहे हैं और जांच की अवधि के दौरान तत्काल पिछले वर्ष की तुलना में कटौती में वृद्धि हुई है। पीयूसी के आयात की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री मूल्य से कम होने की स्थिति दर्शाती है कि पीयूआई के आयात भी कम कीमत पर रहा था क्योंकि पीयूआई कुछ भी नहीं लेकिन सीकेडी / एसकेडी स्थिति में पीयूसी के आयात है।
69. प्राधिकारी मानते हैं कि परिवर्चना प्रक्रिया के माध्यम से पीयूसी की उल्लेखित कम कीमत वास्तव में घरेलू उद्योग के मूल्य निर्धारण प्रतिकूल असर डाला है।

पीयूसी की पहुंच कीमत तथा पीयूआई व कीमत प्रभाव

70. डीजीसीआईएंडएस द्वारा उपलब्ध कराए गए लेनदेन के अनुसार आयात आंकड़ों के आधार पर पीयूसी और पीयूआई के पहुंच मूल्य की गणना की गई है। नीचे दी गई तालिका पहुंच मूल्य की गणना दर्शाती है।

विवरण	इकाई	पीयूसी	पीयूआई
पहुंच मूल्य	रु./किग्रा	#132.74	122.51
घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति	रु./किग्रा	***	***
कीमत में कटौती	रु./किग्रा	***	***
कीमत में कटौती	%	***	***
कीमत में कटौती	% श्रेणी	0-5	5-10

पीयूसी के पहुंच मूल्य में लागू पाटन रोधी शुल्क शामिल है।

71. भारत में लागू पाटन रोधी शुल्क के भुगतान के बाद पीयूसी आया, जबकि पीयूआई को बिना किसी पाटन रोधी शुल्क के आयात किया गया था। यह नोट किया जा सकता है कि पीयूसी की भारत में पहुंच कीमत 132.74 रुपये प्रति किग्रा., पीयूआई की भारत में पहुंच कीमत 98.79/किग्रा और उसके बाद लगभग *** % के मूल्यवर्धन पर विचार

करते हुए, संयुक्त पीयूआई की पहुंच कीमत 1 22.51 रु. /किग्रा. बनी रही। पीयूसी और पीयूआई की पहुंच कीमत में ऐसा अंतर पाटनरोधी शुल्कों की चोरी के प्रभाव को दर्शाता है और ऐसे मूल्य अंतरों के कारण लागू पाटनरोधी शुल्कों का परिवंचना स्पष्ट है। इसके अलावा, आयातकों द्वारा इस तरह की गतिविधियों ने एडीडी उपायों की प्रभावकारिता को कम कर दिया है।

ज. प्रकटीकरण पश्चात् टिप्पणियां

72. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क) प्रकट किए गए तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि चीन जन.गण से आयात किए जा रहे पीयूआई सीकेडी/एसकेडी स्थिति में 'एक्सल फॉर ट्रेलर्स' को 'ट्रेलर एक्सल के हिस्से' के रूप में घोषित करके आयात के अलावा और कुछ नहीं हैं। प्राधिकारी अंतिम जांच परिणाम में विचाराधीन उत्पाद और पीयूआई पर अपनी टिप्पणियों की पुष्टि करें।
- ख) केवल यॉर्क ने आगे आकर इस मामले में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक के रूप में प्राधिकारी के साथ सहयोग किया है। यॉर्क स्पष्ट रूप से स्थायी अपेक्षाओं को पूरा करता है क्योंकि इसका कुल भारतीय उत्पादन में एक बड़ा हिस्सा है और कृपया अंतिम जांच परिणाम में इस जांच से संबंधित पात्र घरेलू उद्योग के रूप में यॉर्क की पुष्टि की जानी चाहिए।
- ग) प्रकट किए गए तथ्य यह साबित करते हैं कि व्यापार के पैटर्न में पीयूसी के आयात से पीयूआई में एक उल्लेखनीय बदलाव आया था और इस तरह का बदलाव शुल्कों को कम करने के लिए था और लागू शुल्कों की चोरी के अलावा ऐसी बदलावों के लिए कोई आर्थिक औचित्य नहीं है।
- घ) वर्तमान मामले के तथ्य यह स्पष्ट करते हैं कि पीयूसी पर एडीडी को पीयूआई के रूप में परिभाषित सीकेडी/एसकेडी स्थिति में आयात करके परिवंचना किया जा रहा है और यह न्याय संगत तथा उचित है कि पीयूसी के आयात पर भी पीयूसी पर शुल्क लागू किया जाए।
- ड.) यह बहुत स्पष्ट है कि इस तरह के शुल्कों से बचने के लिए एडीडी अधिरोपित करने के बाद परिवंचना की प्रक्रिया आरम्भ हुई या तेज हो गई और इस मामले में परिवंचना के परिणामस्वरूप, कर्तव्यों के उपचारात्मक प्रभाव अत्यधिक कम हो गए हैं। परिवंचना ने स्पष्ट रूप से घरेलू उद्योग द्वारा बाजार हिस्सेदारी में अधिक लाभ को रोका और कटौती के स्तर पर ऐसे आयातों की पहुंच कीमत ने घरेलू उद्योग द्वारा उचित मूल्य वृद्धि को रोका जो अन्यथा हुआ होता।
- च) प्रकट किए गए तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि मूल्यवर्धन 35% की सांविधिक सीमा से काफी कम रहा है और यह भी स्पष्ट है कि पीयूआई का आयात पाटित स्तरों पर हो रहा था। परिवंचना करने वाले आयात घरेलू उद्योग की कीमत में उस महत्वपूर्ण स्तर तक कटौती कर रहे थे जिससे कि परिवंचन द्वारा प्राप्त कीमत क्षति स्पष्ट है।
- छ) लागू शुल्कों के लाभ को स्पष्ट रूप से कम करके आंका गया था क्योंकि लागू पाटन को शामिल करने के बाद भी घरेलू उद्योग के एनएसआर से कम कीमत पर पाटित की गई और बाधित सामग्री भारत में पहुंच गई थी।
- ज) तथ्यात्मक प्रकटीकरण से यह स्पष्ट है कि मेसर्स एचडी ट्रेलर्स प्राइवेट लिमिटेड स्पष्ट रूप से प्राधिकारी के साथ सार्थक सहयोग करने में विफल रहा है और पार्टी ने केवल निराधार दावे करने का सहारा लिया है। तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि एचडी ट्रेलर्स प्राइवेट लिमिटेड अपने दावों को सहायक साक्ष्यों के साथ प्रमाणित नहीं कर सका और हम प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि जहां कहीं, उक्त आयातक के निराधार दावों को खारिज करते हुए अंतिम जांच परिणाम के प्रयोजन के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध जानकारी पर भी विचार करें।
- झ) तथ्यों से यह स्पष्ट है कि मामला परिवंचना शुल्क की सिफारिश करने के लिए सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है क्योंकि (क) जांच के तहत संचालन आरम्भ हुआ या बढ़ाया गया, या उसके ठीक पहले, पाटन रोधी जांच और पुर्जों और घटकों का आयात किया जाता है। पाटन रोधी शुल्क लगाने के उद्देश्य से अधिसूचित मूल देश या निर्यात का देश, (ख) संयोजन या समापन संचालन के दौरान लागू हुए इनपुट में जोड़ा गया मूल्य, विनिर्माण लागत के 35% से कम है, (ग) पीयूआई का आयात, जो

सीकेडी/एसकेडी की स्थिति में पीयूसी के अलावा और कुछ नहीं है, पाटित दरों पर बनी है, (घ) शुल्क से बचकर पीयूआई के आयात ने पीयूसी पर लगाए गए एडीडी के उपचारात्मक प्रभाव को कम कर दिया है और (ङ.) पीयूआई का आयात केवल लागू शुल्क से बचने के लिए किया गया था।

ज.) घरेलू उद्योग पर परिवर्चना और इसके प्रतिकूल प्रभावों को प्रदर्शित करने वाले प्रकट किए गए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी चीन जन.गण से पीयूआई के आयातों पर भी पीयूसी पर एडीडी के विस्तार की सिफारिश कर सकते हैं।

73. मेसर्स एचडी ट्रेलर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क) मेसर्स एचडी ट्रेलर्स प्राइवेट लिमिटेड की विशिष्ट जांच के साथ-साथ विचार करने के अनुरोध पर विचार नहीं किया गया है। मेसर्स एचडी ट्रेलर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मांगे गए विवरण और दस्तावेजों को अस्वीकार कर दिया गया है और इस प्रकार इसे मामले का सही और प्रभावी प्रतिनिधित्व करने से प्रभावी रूप से रोक दिया गया है। तथापि, मेसर्स यॉर्क ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट के प्रथकन को बिना किसी प्रमाण के ले लिया गया है।

ख) यॉर्क की पुस्तिकाओं के लिए अनुरोधित फॉरेंसिक लेख परीक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया है। यह बताया गया है कि यॉर्क की पुस्तिकाओं में हेराफेरी की गई है। साथ ही, यॉर्क और उसके संबंधित पक्षों द्वारा किए गए आयातों की जांच नहीं की गई है।

ग) यॉर्क द्वारा एक्सल के उत्पादन और खपत का पता लगाने के लिए अपनाया गया फॉर्मूला दोषपूर्ण है।

घ) यॉर्क विनिर्माण गतिविधि को अपना रहा है जो एचडी ट्रेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के समान है।

ङ.) जहां तक मेसर्स एचडी ट्रेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के वर्कशीट और बैलेंस शीट के आंकड़ों से कथित भिन्नता है, यह भ्रम पूरी तरह से कंपनी की गतिविधियों की प्रकृति को समझने में प्राधिकारी की ओर से विफलता के कारण है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राधिकारी ने स्पष्टीकरण मांगे बिना तथ्यों पर कार्यवाही की है।

च) मेसर्स एचडी ट्रेलर्स प्राइवेट लिमिटेड न केवल ट्रेलर एक्सल बनाती है बल्कि सस्पेंशन भी बनाती है, जो एडीडी के स्कोप से पूरी तरह बाहर है। इसी तरह, आयातित सामान न केवल पीयूसी और पीयूआई हैं, बल्कि सस्पेंशन के हिस्से भी शामिल हैं। प्राधिकारी द्वारा बैलेंस शीट में दिए गए विनिर्माण विवरण को ट्रेलर एक्सल के रूप में और आयात के आंकड़ों को केवल पीयूआई के आयात के रूप में लेने के कारण भ्रम हुआ है।

छ) जहां तक मूल्यवर्धन के मुद्दे का संबंध है, नियम 26 के खंड (ii) में दिया गया 'मूल्य' मूल्य को आयातित भागों या घटकों के मूल्य को घटाकर असेंबल या तैयार वस्तु की लागत के रूप में परिभाषित करता है। इस प्रकार, यह नियम असेंबल, पूर्ण या तैयार वस्तु की लागत और आयातित भागों या घटकों के मूल्य पर विचार करना निर्धारित करता है।

ज) मेसर्स एचडी ट्रेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में, आयातित सामान के मूल्यवर्धन को असेम्बल्ड वस्तु की कुल लागत और आयातित माल की लागत के बीच के अंतर के रूप में माना जाना चाहिए, जो कि 859.00 लाख रु. (1855.87 और 996.87 के बीच का अंतर) है। इस प्रकार, 859.00 लाख रुपये की राशि जब आयातित घटकों की लागत के % के रूप में ली जाती है, तो यह 86.17 % हो जाती है जो कि 35% की सीमा से कहीं अधिक है। अतः चकबंदी का प्रश्न ही नहीं उठता।

झ) मुद्दा यह है कि क्या भारत में आयात किए गए ट्रेलर एक्सल पर लगाए गए पाटन रोधी शुल्क का परिवर्चना है और जांच को केवल मेसर्स एचडी ट्रेलर्स प्राइवेट लिमिटेड तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए।

74. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अधिकांश अनुरोध दोहराए जाने वाली प्रकृति के हैं। अंतिम जांच परिणाम में इन अनुरोधों की जांच पहले से ही उपयुक्त स्थानों पर कर ली गई है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों के अतिरिक्त/नए प्रासंगिक अनुरोधों की निम्नानुसार जांच की है:

- क) मेसर्स एचडी ट्रेलर्स प्रा. लिमिटेड के तर्क के संबंध में कि उनके अनुरोधों पर विचार नहीं किया गया था और उनके द्वारा मांगे गए दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए थे, प्राधिकारी नोट करते हैं कि तर्कों में कोई बल नहीं है। प्राधिकारी ने नियम के तहत आवश्यक साक्ष्य के साथ समर्थित सभी अनुरोधों पर विचार किया है और उन्हें संबोधित किया है और केवल तथ्यों या कानून द्वारा समर्थित नहीं होने वाले तर्कों को खारिज कर दिया गया है। हितबद्ध पक्षों को अन्य हितबद्ध पक्षों के साथ अपने अनुरोधों के अगोपनीय संस्करण का आदान-प्रदान करने के लिए कहा गया है और इसे देखते हुए, यह तर्क कि प्राधिकारी ने दस्तावेजों तक पहुंच से इनकार कर दिया है, को भी खारिज कर दिया जाता है।
- ख) प्राधिकारी नोट करते हैं कि जबकि यॉर्क को मूल जांच में घरेलू उद्योग के रूप में पाया गया था, मेसर्स एचडी ट्रेलर्स प्रा. लिमिटेड ने स्वयं को विचाराधीन उत्पाद के एक आयातक के रूप में पंजीकृत किया और एक आयातक प्रभावली का उत्तर दर्ज किया। तथापि, मौजूदा परिवंचना रोधी मामले में, मेसर्स एचडी ट्रेलर्स प्रा. लिमिटेड ने विरोध किया है कि यह उसी तरह की विनिर्माण गतिविधि कर रहा है जैसा कि यॉर्क, जो वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग है, विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए अपना रहा है।
- ग) हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त टिप्पणियों के को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने मेसर्स एचडी ट्रेलर्स प्रा. लिमिटेड की किए गए विवादों और इसके द्वारा की जा रही निर्माण प्रक्रिया को समझने के लिए कोविड-19 के मद्देनजर डिजिटल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विचार विमर्श और पुष्टिकरण की। विचार-विमर्शों से यह सामने आया कि मेसर्स एचडी ट्रेलर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पी. ओ. आई. के दौरान की जाने वाली गतिविधि की प्रकृति आयातक स्वरूप की है जबकि पीयूसी के आयात पर मौजूदा पाटन-रोधी शुल्कों की चल रही सनसेट समीक्षा में, कंपनी ने खुद को एक निर्माता/निर्माता होने का दावा किया है। कई अनुरोधों के बावजूद पक्ष, जांच की अवधि के दौरान स्वयं को पीयूसी के निर्माता के रूप में स्थापित करने के लिए कोई निर्णायक प्रमाण रिकॉर्ड नहीं रख सकी। यह आगे नोट किया गया है कि कंपनी के कानूनी प्रतिनिधि ने भी स्वीकार किया कि कंपनी धीरे-धीरे विनिर्माण गतिविधि की ओर बढ़ रही है जो कि इस परिवंचना-रोधी जाँच के दायरे से बाहर है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मेसर्स एचडी ट्रेलर्स प्रा. लिमिटेड का दावा कि उनके द्वारा की गई विनिर्माण गतिविधि यॉर्क के समान है, को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
- घ) इस तर्क के संबंध में कि यॉर्क की पुस्तिकाओं की फॉरेंसिक लेखा परीक्षा पर विचार नहीं किया गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग और अन्य विरोधी पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुरोधों और दस्तावेजों पर उचित जांच और प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई प्रथाओं के अनुसार सत्यापन के बाद ही विचार किया गया है। इसके अलावा, जांच का दायरा यह स्थापित करना है कि परिवंचना को क्या मौजूदा पाटन-रोधी शुल्कों की प्रभावकारिता को कमजोर करने के लिए किया गया है।
- ड.) इस तर्क के संबंध में कि यॉर्क द्वारा एक्सल के कुल भारतीय उत्पादन का पता लगाने के लिए अपनाया गया फॉर्मूला दोषपूर्ण है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राइम मूवर्स के उत्पादन से संबंधित सियाम आंकड़ों के आधार पर कुल एक्सल आवश्यकता की गणना करने के लिए वर्तमान जांच में अपनाए गए फॉर्मूले को मूल जांच में भी उचित पाया और अपनाया गया था। विरोधी पक्षकारों द्वारा यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया है कि ऐसा फॉर्मूला पूरी तरह से तर्कहीन है। आगे यह भी नोट किया गया है कि भले ही $80\% \times 2.5$ एक्सल और $20\% \times 3$ एक्सल के फार्मूले को परम्परागत दृष्टिकोण के रूप में माना जाता है, फिर भी सियाम आंकड़ों के आधार पर कुल भारतीय उत्पादन में अकेले यॉर्क के पास 76 प्रतिशत का एक बड़ा हिस्सा है। सियाम आंकड़े दर असल विरोधी पक्षों द्वारा विवादित नहीं है।
- च) एचडी ट्रेलर्स के इस तर्क के संबंध में कि इसकी वर्कशीट और बैलेंस शीट के आंकड़ों में कथित बदलाव प्राधिकारी के भ्रम के कारण हैं, यह नोट किया जाता है कि निर्धारित विभिन्न प्रारूपों में आवश्यकताएं पक्षों की मदद करने के लिए बहुत विशिष्ट हैं। अपनी लेखापरीक्षित बहियों के अनुरूप प्रासंगिक सूचना प्रदान करते हैं और प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना पर विचार किया है और उसका विश्लेषण किया है। इसलिए, यह तर्क कि प्राधिकारी सूचना के साथ भ्रमित हो

रहा है, कोई प्रासंगिकता नहीं है। प्राधिकारी ने पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए रिकॉर्ड से पीयूआई और अन्य से संबंधित जानकारी पर उचित रूप से विचार किया।

छ) मैसर्स एचडी ट्रेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के तर्क के संबंध में कि मूल्य संवर्धन की गणना प्रकटीकरण बयान या तो कानूनी तौर पर या तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कैसे एक परिवंचना रोधी जांच के संदर्भ में मूल्य संवर्धन की गणना करने के लिए स्पष्ट रूप परिवंचना रोधी नियम में प्रदान किया जाता है और उसे ही प्राधिकारी द्वारा अपनाया गया है। इस प्रकार, मूल्यवर्धन के संबंध में प्रकटीकरण विवरण में प्रकट किए गए तथ्य सही कानूनी स्थिति को दर्शाते हैं। प्राधिकारी ने मूल्य संवर्धन गणना पर एचडी ट्रेलर्स द्वारा तथ्यात्मक खंडन की जांच की है और नोट करते हैं कि तथ्यों का पहले खुलासा किसी भी संशोधन का वारंट नहीं करते क्योंकि एच डी ट्रेलर्स द्वारा पहले गणना में संशोधनों को सही ठहराने के लिए कोई भी नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

ज) मैसर्स एचडी ट्रेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के तर्क के संबंध में कि परिवंचना की जांच केवल एचडी ट्रेलर्स प्राइवेट लिमिटेड तक सीमित नहीं होनी चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान परिवंचना रोधी जांच के परिणाम विचाराधीन उत्पाद के सभी चक्रमा देने वाले आयातों पर लागू होंगे और केवल किसी विशेष आयातक तक सीमित नहीं होंगे।

झ) घरेलू उद्योग के दावों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनुरोध उनके पहले के दावों की पुनरावृत्ति हैं और इसलिए उन्हें अलग से संबोधित नहीं किया गया है।

झ. निष्कर्ष

75. सीमा शुल्क आयुक्त, न्हावा शेवा से इनपुट के आधार पर वर्तमान जांच आरम्भ करने और घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षों के तर्कों की जांच करने के बाद और उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी निम्नानुसार निष्कर्ष निकालते हैं:

क) पीयूसी पर पाटन रोधी शुल्क अधिरोपित होने के बाद चीन जन.गण से पीयूसी और पीयूआई के आयात के मामले में व्यापार की पद्धति में बदलाव आया है।

ख) पीयूआई (पूर्ण नॉक डाउन/सेमी नॉक डाउन कंडीशन में ट्रेलर्स के लिए एक्सल) को पीयूसी (ट्रेलर्स के लिए एक्सल) में परिवर्तित करने में मूल्यवर्धन, परिवंचना-रोधी नियमों में निर्धारित सीमा से काफी कम है।

ग) चीन जनवादी गणराज्य से पीयूआई का आयात पाटित कीमतों पर होता रहा है।

घ) सीमा शुल्क अधिसूचना सं.54/2016-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 29 नवंबर, 2016 के तहत अधिरोपित पीयूसी पर मौजूदा पाटन-रोधी उपाय के उपचारात्मक प्रभाव को पीयूआई के आयात ने कम किया है।

अ. सिफारिशें

76. प्राधिकारी ने उपर्युक्त तथ्यात्मक मैट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए;

क) चीन जन.गण के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पीयूआई के आयात पर केंद्र सरकार द्वारा 29 नवंबर, 2016 की अधिसूचना संख्या 54/2016-सीमा शुल्क (एडीडी) के तहत चीन जन.गण के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ट्रेलर्स के लिए एक्सल के आयातों पर लगाए गए मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के विस्तार की सिफारिश की जाती है। (सीमा शुल्क अधिसूचना नं 54/2016-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 29 नवंबर, 2016 में विधिवत तालिकाबद्ध **अनुबंध - I में संलग्न है।**)

ख) पीयूआई पर पाटन रोधी शुल्क की वैधता केंद्र सरकार द्वारा शुल्क की अधिसूचना की तारीख से होगी और चीन जन.गण के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ट्रेलर्स के लिए एक्सल पर शुल्क के साथ सह-समाप्ति पर होगी।

ट. आगे की प्रक्रिया

77. इस अंतिम जांच परिणाम से होने वाले केंद्र सरकार के आदेश के खिलाफ सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील की जाएगी।

अनंत स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

अनुबंध - I

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2016

सं. 54/2016-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. (अ). जबकि, चीन जनवादी गणराज्य (तत्स्थिमन प्रश्नात् जिन्हें विषयगत देश के रूप में संदर्भित किया गया है) में उत्पादित अथवा वहां से निर्यात किए जाने वाले और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (तत्स्थिमन प्रश्नात् जिसे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 8716 90 10 के अंतर्गत आने वाले "टेलर्स के लिए एक्सल", (तत्स्थिमन प्रश्नात् जिन्हें विषयगत वस्तुओं के रूप में संदर्भित किया गया है) जिनका भारत में आयात किया जाता है, के मामले में पदनामित प्राधिकारी, भारत सरकार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I खंड 1 में प्रकाशित दिनांक 30 सितंबर, 2016 की अधिसूचना सं. 14/17/2015-डीजीएडी, के अंतर्गत प्रकाशित अपनी जांच-पड़ताल में निम्नलिखित अनंतिम निष्कर्षों पर पहुंचे हैं कि—

- (क) विषयगत वस्तुओं का विषयगत देशों से सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर भारत में निर्यात किया गया है;
- (ख) घरेलू उद्योग को विषयगत देशों से विषयगत आयात के कारण भारी नुकसान हुआ है;
- (ग) यह नुकसान विषयगत देशों से विषयगत वस्तुओं के डंप आयात के कारण हुआ है;

और उन्होंने घरेलू उद्योग को हुए नुकसान को समाप्त करने के आशय से विषयगत देश में उत्पादित अथवा वहां से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के भारत में किए जाने वाले आयात पर अनंतिम प्रतिपादन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है;

अब, अतः केंद्र सरकार सीमा शुल्क टैरिफ (डंपिंग मदों की पहचान, उनका मूल्य निर्धारण और उन पर प्रतिपादन शुल्क का संग्रहण तथा नुकसान का निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पदनामित प्राधिकारी के उपर्युक्त अनंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात् विषयगत वस्तुओं, जिनका विवरण निम्न तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कॉलम (2) की तदनुरूपी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट किए अनुसार सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के मद के अंतर्गत आती है, कॉलम (4) की तदनुरूपी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट किए गए देशों में उत्पादित होती है, कॉलम (5) की तदनुरूपी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट किए गए देशों से निर्यातित होती है, कॉलम (6) की तदनुरूपी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों द्वारा उत्पादित होती है, कॉलम (7) की तदनुरूपी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्यातकों द्वारा निर्यात की जाती है, के भारत में आयात किए जाने पर, कॉलम (10) की तदनुरूपी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में तथा कॉलम (9) की तदनुरूपी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट पैमाइश की इकाई के अनुसार, कॉलम (8) में सामने दी गई प्रविष्टि राशि के समतुल्य प्रतिपादन शुल्क दर लगाती है, अर्थात्:-

तालिका

क्र.सं.	टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	मूल देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	धनराशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	87169010	ट्रेलर्स के लिए एक्सल	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	गुआंगडोंग फुवा इंजीनियरिंग मैनुफैक्चरिंग कं. लि.	गुआंगडोंग फुवा इंजीनियरिंग मैनुफैक्चरिंग कं. लि.	0.16	किलो ग्राम	अमरीकी डॉलर
2	87169010	ट्रेलर्स के लिए एक्सल	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	गुआंगडोंग फुवा हैवी इंडस्ट्रीज कं. लि.	गुआंगडोंग फुवा हैवी इंडस्ट्रीज कं. लि.	0.16	किलो ग्राम	अमरीकी डॉलर
3	87169010	ट्रेलर्स के लिए एक्सल	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	शानडोंग जिनशेंग एक्सल मैनुफैक्चरिंग कं. लि.	शानडोंग जिनशेंग एक्सल मैनुफैक्चरिंग कं. लि.	0.16	किलो ग्राम	अमरीकी डॉलर
4	87169010	ट्रेलर्स के लिए एक्सल	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	क्रमांक 1 से 3 से इतर कोई भी संयोजन		0.46	किलो ग्राम	अमरीकी डॉलर
5	87169010	ट्रेलर्स के लिए एक्सल	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य से इतर कोई भी अन्य देश	कोई	कोई	0.46	किलो ग्राम	अमरीकी डॉलर
6	87169010	ट्रेलर्स के लिए एक्सल	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	कोई	कोई	0.46	किलो ग्राम	अमरीकी डॉलर

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपादन शुल्क इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 5 वर्ष (जब तक इससे पूर्व रद्द, अधिक्रमित अथवा संशोधित नहीं कर दिया जाए) के लिए लागू होगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जाएगा।

स्पष्टीकरण – ऐसे प्रतिपादन शुल्क की गणना के आशय से लागू विनिमय दर वह दर होगी जो भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 14 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाती हैं और विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख, उक्त सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 46 के अंतर्गत बिल ऑफ एंट्री के प्रस्तुतीकरण की तारीख होगी।

[फा. सं. 354/178/2016-टीआरयू]

अनुराग सहगल, अवर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th September, 2021

FINAL FINDINGS**CASE NO. (AC) 07/2020**

Subject : Final Findings in Anti-Circumvention investigation concerning alleged circumvention of Anti-dumping duty imposed on the imports of 'Axle for Trailers' originating in or exported from China PR.

1. **F. No. 4/11/2020-DGTR.**—Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) thereof.

A. BACKGROUND OF THE CASE

2. WHEREAS, the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), in an antidumping investigation, vide its Final Findings Notification No 14/17/2015-DGAD dated 30.9.2016, had recommended the imposition of anti-dumping duty on the imports of "Axle for Trailers" originating in or exported from China PR (PUC or Subject goods), and the definitive anti-dumping duty was imposed by the Ministry of Finance, vide Customs Notification No. 54/2016-Customs (ADD), dated the 29.11.2016.
3. The Authority had initiated a case *suo-motu* based on the information received from the Commissioner of Customs (Imports) NS-V Jawaharlal Nehru Custom House, Nhava Sheva, Uran, District Raigarh, Maharastra under rule 26(3) of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping on Dumped Articles and for Determination of Injury) Amendment Rules, 1995. While the importer identified in the Commissioner of Customs letter to DGTR did not file any response in the investigation, M/s. H.D. Trailers (an importer in the original investigation) filed a response which the Authority has analysed on various data aspect and legal submissions. The Authority has therefore, based its analysis on the data filed by the Domestic Industry and the importer as required under the relevant Anti-circumvention rules.
4. In view of the above Authority initiated the investigation under Rule 26 which states as below;

"26. Initiation of investigation to determine circumvention. -

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the designated authority may initiate an investigation suo motu if it is satisfied from the information received from the Commissioner of Customs appointed under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) or any other source that sufficient evidence exists as to the existence of the circumstances pointing to circumvention of anti-dumping duty in force."

5. WHEREAS, by taking cognizance of the information provided by the Commissioner of Customs as per sub rule 3 of Rule 26 of the Anti-dumping rules, the Authority initiated the subject anti-circumvention investigation vide Notification F. No. 4/11/2020-DGTR- dated 15th September, 2020 to determine the existence, degree and effect of the alleged circumvention of the Anti-dumping duties levied on the subject goods by way of import of Product Under Investigation (hereinafter referred to as PUI) and to consider recommendation of extension of existing antidumping duty also on such imports of PUC in CKD/SKD condition from China PR, in accordance with relevant AD Rules.

B. PROCEDURE

6. The procedure described herein below has been followed with regard to the subject investigation.

- i. The Authority notified the Embassy of China PR about the Anti-Circumvention investigation in accordance with the Customs Tariff Act read with Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995.
- ii. The Authority, issued a public notice dated 15th September, 2020 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating anti-circumvention investigation concerning imports of PUI from China PR.
- iii. The Authority forwarded a copy of the initiation notice to Embassy of China PR in India, all known exporters of PUC/PUI, importers in India as per the information available on records.
- iv. The Authority wrote to the exporters/ producers of the PUC/PUI and requested them to file their responses in the prescribed questionnaire and make their views known in writing within the time limit prescribed. Copies of the letter and questionnaires sent to the exporters were also sent to the Embassy of China PR, along with a list of known exporters/ producers, with a request to advise the exporters/ producers to respond to the Authority within the prescribed time.
- v. The Authority sent questionnaires to elicit relevant information to the following known producers/exporters in China PR in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:
 - a) Guangdong FUWA Engineering Manufacturing Co., Ltd.
 - b) Guangdong FUWA Heavy Industries Co., Ltd.
 - c) Shandong Jinsheng Axle Manufacturing Co., Ltd.
- vi. None of the producers/exporters from China PR have filed the exporter's questionnaire response/submissions. Accordingly, the producers/exporters from China PR are being treated as non-cooperative in this investigation.
- vii. Questionnaires were also sent to the following known importers/users of the subject goods in India seeking necessary information in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules.
 - a) King Kaveri Trading Company
 - b) H.D. Trailers Pvt. Ltd.
 - c) Satrac Engineering Private Limited
 - d) Safetech Trailer Parts LLP
 - e) Synergic Trailer and Auto Solutions Pvt. Ltd.
 - f) Shivam Motors Pvt. Ltd.
 - g) Black Diamond Motors Pvt. Ltd.
 - h) Vandana Trailors & Body MFG (P) Ltd.
 - i) MS Trailer Parts LLP.
- viii. In response to the initiation notification, following importers/users filed the response;
 - a) H.D. Trailers Pvt. Ltd.
- ix. Initiation notification was also sent to the following known producers of the subject goods in India as per the records of the original investigation;
 - a) M/s. York Transport Equipment (India) Pvt. Ltd.
 - b) M/s. Tata Motors Ltd.
 - c) M/s. Ashok Leyland Ltd.
 - d) M/s. JOST India Auto Component Pvt. Ltd.
 - e) M/s. G.S. Auto International Ltd.

- x. In response, M/s York Transport Equipment (India) Pvt. Ltd, claiming to be the largest producer of subject goods in India, supported the initiation and provided relevant information and requested the Authority to treat them as the domestic industry for all practical purposes of the present investigation. The other producers have neither supported nor opposed the present investigation.
- xi. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties to the other parties by way of directions to exchange the submissions via e-mail as physical verification of the Public File is not permissible on account of the ongoing pandemic. Submissions made by all the interested parties to the extent considered relevant have been taken into account in these final findings.
- xii. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claim, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information.
- xiii. Further information was sought from interested parties to the extent deemed necessary.
- xiv. Investigation was carried out for the period starting from April, 2019 to March, 2020 (12 months) (hereinafter referred to as the “period of investigation” or “POI”). The examination of trends, in the context of injury analysis covered the period from 2016-17, 2017-18, 2018-19 and the POI.
- xv. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide the details of imports of PUC and PUI during the last four years, including the period of investigation, and the same was received by the Authority. The Authority has used the DGCI&S import data for computation of the volume and value of imports and injury analysis.
- xvi. In accordance with Rule 6(6) of the Anti-Dumping Rules, the Authority provided opportunity to the interested parties to present their views orally in a hearing held through Video Conferencing on 10th December, 2020. All the parties were requested to submit their written submissions and the rejoinder to the written submissions following the oral hearing. Due to a change in the Designated Authority, another oral hearing was held via Video Conferencing on 22nd February, 2021 and all the interested parties were given further opportunities to file written and rejoinder submissions, if any.
- xvii. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigations, or has significantly impeded the investigation, the Authority has recorded its observation on the basis of the facts available.
- xviii. A Disclosure Statement was issued on 09.08.2021 disclosing essential facts under consideration of the Designated Authority to the interested parties and granting time up to 12.08.2021 to furnish comments, if any, on the Disclosure Statement. Post disclosure comments received from the interested parties have been examined and considered appropriately at relevant paras of these final findings.
- xix. ‘***’ in these final findings represents information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.
- xx. Exchange rate considered for the POI for conversion of USD to Indian Rupees is 1USD=Rs. 71.65

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION/ PRODUCT UNDER INVESTIGATION AND LIKE ARTICLE

C.1. Product Under Consideration

- 7. The product under consideration is the same as defined in the earlier investigation i.e. “Axle for Trailers” originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as PUC or Subject

goods). It falls under Customs Tariff 87169010 of the First Schedule to the Customs Tariff Act 1975. The Anti-dumping duty on imports of PUC from China PR is in force till 28.11.2021.

8. The subject goods are manufactured and sold in different variants. However, the basic product characteristics and end use of all these variants remains the same and all such types of Trailer Axles have been covered in the scope of the PUC. All such variants essentially constitute a homogenous product under consideration with comparable basic characteristics and similar functions/uses.

C.2. Product Under Investigation

9. The Product Under Investigation (hereinafter also referred to as PUI) is the subject good in CKD (complete knock down)/SKD (semi knock down) conditions which is being imported by declaring it as 'parts of trailer axles' and which is allegedly circumventing the anti-dumping duty in force on imports of PUC from China PR.

C.3 Views of the Domestic Industry

10. The domestic industry has made following submissions with regard to the scope of product under consideration and the like article:
 - a) PUC and PUI are well defined in the initiation and the facts of the case make it evident that PUI is nothing but mere imports of PUC in CKD/SKD condition.
 - b) Axle for Trailers are getting imported in CKD (complete knock down)/SKD (semi knock down) condition by declaring it as parts of trailer axles with an intention to avoid ADD on 'Axle for Trailers' and the definition of PUI adopted fully reflects such practices being followed by some importers.
 - c) The definition of PUC and PUI makes it evident that imports of PUI warrants ADD applicable at the time of imports of 'Axle for Trailers' to be extended to such imports of PUI.
 - d) PUI are nothing but PUC in CKD/SKD condition. Such imports have no other justification other than evasion of ADD on PUC. PUI thereafter is assembled as PUC with very minimal value addition that the circumvention is very evident.
 - e) HD Trailers have been trying to justify circumvention by coining an argument that they have been importing single piece seamless beams which as per them is a superior product as the beams available in India are 3 piece welded beam. The contention has no basis or merit.
 - f) Single piece beam cannot be considered as a superior product in any manner and is a clearly competing product with the axles made in countries like India. Single Piece Beams are not used prominently in Global Market. It is only used by Chinese manufacturers. None of the Indian Truck manufacturers uses this single piece beam technology in India. Three piece welded beam are proven internationally. Also bigger OEMs like TATA Motors & Ashok Leyland are using these 3 piece welded beam in their commercial vehicle Non drive axles/ tag axles & also trailer axles. Thus, the motive of importing such product is still evasion of ADD and there are no other bona fide reasons for such imports. Import of seamless single piece beam no way justifies circumvention as being done in the present matter.

C.4 Views of the Opposing Interested Parties

11. The views of the opposing interested parties are summarised below:
 - a) It has been submitted by HD Trailers Pvt Ltd in their Importer Questionnaire Response that they import Axle Beam, Cam Shaft, Cam Set, Slack Adjuster, Hub Cap only.
 - b) The activity of H D Trailers Pvt Ltd is to assemble PUI imported along with local materials to produce PUC as submitted in their IQR.

- c) The axle beam tube is a vital part for the axle. The tube used by the rest of the manufacturers is consisting of more than one part joined by welding. The tubes we import are seamless and thus have more strength. None of the Indian producers make the seamless tube. Likewise the hubcap of the imported material is of unique design which is far superior to that of the indigenous product. For these reasons the imported product is sold at a higher price than that of York.

C.5 Examination by the Authority

12. The present investigation is an anti-circumvention investigation concerning duties imposed on imports of 'Axle for Trailers' originating in or exported from China PR. Therefore, the scope of the product under consideration as defined in the last concluded anti-dumping investigation remains applicable for the present investigation also.
13. The product under consideration is the same as defined in the earlier investigation i.e. "Axle for Trailers" originating in or exported from China PR. It falls under Customs Tariff Head 87169010 of the First Schedule to the Customs Tariff Act 1975. The above-stated classification of the products under investigation, however, are indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation. The Anti-dumping duty on imports of PUC from China PR is in force till 28.11.2021.
14. The subject goods are manufactured and sold in different variants. However, the basic product characteristics and end use of all these variants remains the same and all such types of Trailer Axles have been covered in the scope of the PUC. All such variants essentially constitute a homogenous product under consideration with comparable basic characteristics and similar functions/uses.
15. The Authority notes that the anti-dumping duty in force on imports of PUC from China PR is allegedly being circumvented by imports of PUC in CKD (complete knock down)/SKD (semi knock down) conditions and by declaring them as 'parts of trailer axles.' As per the import data, imports of PUI covers parts like Axle Beam, Cam Shaft, Cam Set, Slack Adjuster, Hub Cap, Brake Drum etc. It is noted from the information available that the said imported PUI are being assembled to manufacture PUC and that the parts alone have no other known uses. Since the purpose of imports of PUI are for such assemblage only and manufacture of PUC thereof, therefore it is leading to circumvention of the existing anti-dumping duties on the PUC.
16. The Authority notes from the information on records that the product under consideration produced by the domestic industry is "like article" to the goods imported from the subject country. The product under consideration produced by the Indian industry and imported from the subject countries are comparable in terms of technical specifications, functions or end-use product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably.
17. The Authority holds that the PUI as above getting imported from China PR are nothing but imports of 'Axle for Trailers' in CKD (complete knock down)/SKD (semi knock down) condition by declaring it as 'parts of trailer axles.'
18. With regard to the contention of the opposing party that Axle Beam import is made out of a single seamless tube and is a superior product in comparison to the three-piece beam supplied by the Indian producers, the Authority notes from the available information that the said single piece beam cannot be considered as a different product from what is covered in the PUC. Axle for Trailers manufactured out of a single piece beam or a welded beam is comparable products and they can be used as a direct substitute for the other as per the submissions made by the Indian producer. Thus, the contention cannot be a ground to exclude single piece beam from the scope of PUC/PUI as a different product from the PUC which has been subjected to anti-dumping duties.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1 Views of the Domestic Industry

19. M/s York Transport Equipment (India) Pvt. Ltd. has made following submissions with regard to domestic industry and standing;

- a. It is requested that M/s York Transport Equipment (India) Pvt. Ltd be treated as the domestic industry for the purposes of present investigation as it holds a major proportion of the Indian production of the subject goods and it fully supports the present investigation.
- b. The Company was treated as the domestic industry in the original investigation also. The basis of estimate of total Indian production adopted by York is consistent with the original finding of the Authority and it would be apparent that York holds major share in Indian production of subject goods.
- c. The Company has also certified that it did not import the subject goods from China PR along with declarations on related parties in India and China PR relevant for the present investigation. Details of any related parties in countries other than China PR are also available in the Annual Report of the Company though such detail has no relevance in the present investigation.
- d. HD Trailers Pvt Ltd cannot be considered as part of domestic industry and bona fides of claims of HD Trailers Pvt Ltd. as domestic producer of PUC needs examination.
- e. HD Trailers Pvt Ltd has been one of the largest importers who has resorted to rampant circumvention of ADD by starting an assembling facility and the nature of business of HD Trailers is clearly that they are engaged in the circumvention of the duty very openly.
- f. The increase in import of PUI by HD Trailers Pvt. Ltd. shows such practice and it needs to be also noted that the imports of the PUC have become nil by the POI as declared by the aforementioned company.
- g. It is incumbent on HD Trailers to prove that they did not engage in circumvention practices and until and unless the same is proved, they cannot be considered as part of domestic industry. The Company has claimed that they are in favour of extending the duties to PUI to ensure the benefits of duties are not vitiated. However, the response by HD Trailers shows that they have been importing major parts and in such case disproving circumvention shall be simply impossible.
- h. To examine the genuineness of the claim of HD Trailers as Indian producer of the subject goods, the Authority must check and compare the capital investments made by York and HD Trailers to produce the subject product and details of plant and machinery and other details deployed by both the companies so that authenticity of the claims can be verified. As it stands, no such information is provided by HD Trailers apart from a list of machine names of which is not disclosed and we cannot offer any comments on the same.
- i. The investment made by HD Trailers is apparently for an assembling unit and it has no capabilities to produce the subject goods like York and no such investments have been made by the company as a bona fide manufacturer of Axle for Trailers.
- j. York satisfies the standing requirement and constitutes domestic industry within the meaning of the AD Rules.

D.2 Views of the other Interested Parties

20. The following submissions have been made by other interested parties with regard to standing and scope of domestic industry;

- a) M/s. York Transport Equipment (India) Ltd appears to be having business relationship with its own group companies having imports and exports between them. In addition to this, other entities also have joined with them and formed a consortium though legally such an arrangement is kept outside the legal requirement of declaration of such associations. This results in the import of parts in different names and utility of the same by other entities.

- b) Calculation of axle requirement by applying the formula of $10\%*1 + 80\%*2 + 10\%*3$ is not correct. The formula to be applied is $1\%*1 + 30\%*2 + 69\%*3$. When this correct formula is applied, the share of York would considerably change.
- c) 69% of the inputs of the product Trailer Axle manufactured by HD Trailers now are indigenous and hence we request that HD Trailers be considered as an Indian manufacturer and not as an importer.
- d) H.D. Trailers Pvt. Ltd. has established its factory for the manufacture of trailer axles much earlier to the imposition of ADD on trailer axles and now around 69% of the components of the trailer axle are indigenous.

D.3 Examination by the Authority

21. Since the present investigation was initiated based on information from the Customs Authority, identification of domestic industry for the purpose of present investigation was not essential at the stage of initiation. However, the known producers of the subject goods in India based on the previous investigation were intimated about the investigation and relevant information was sought from such parties. It is noted that only M/s York Transport Equipment (India) Ltd has responded to the initiation notice and made request to treat them as the domestic industry for the purpose of the present investigation. The Company has also provided the required information. It is also noted that M/s York Transport Equipment (India) Ltd was determined as the domestic industry concerning the subject goods in previous investigation.

22. It is noted that rule 26 (1) and 26(3) of Anti-dumping rules read as under:

Rule 26(1): Except as provided here in below the designated authority may initiate an investigation to determine the existence and effect of any alleged circumvention of the anti-dumping duty levied under section 9A of the act upon receipt of a written application by or on behalf of the domestic industry,

Rule 26(3): Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the designated authority may initiate an investigation suo motu if it is satisfied from the information received from the Commissioner of Customs appointed under the Customs Act 1962 (52 of 1962) or any other source that sufficient evidence exists as to the existence of circumstances pointing to circumvention of anti-dumping duty in force.

23. The Authority initiated the subject investigation *suo-motu* under Rule 26 (3) based on the information received from the Commissioner of Customs (Imports), Nhava Sheva.

24. With regard to the contention that the relation of M/s York Transport Equipment (India) Ltd. to the importers/exporters must be examined, the Authority notes that M/s York Transport Equipment (India) Ltd has certified that they did not import the subject goods from China PR themselves or through any of the related parties.

25. With regard to the claim of H.D. Trailers Pvt. Ltd to consider them in the scope of domestic industry, the Authority notes that no substantial information is provided by the Company to substantiate such claims. The Company has filed deficient information in the importer questionnaire format which shows the company have been importing PUI from China PR in the entire injury period. The conduct of the Company has been of an importer of PUI and in view of the same H.D. Trailers Pvt. Ltd cannot be considered in the scope of domestic industry.

26. With the regard to the contentions of M/s H.D. Trailers Pvt. Ltd. that the total Indian production claimed by the domestic producer and the method adopted to calculate such production is not correct, the Authority recalls its finding on such calculations adopted in the original investigation of this matter. The methodology then adopted is reproduced below and a similar approach has been adopted in the present matter also as there are no material facts adduced by any party to change the above methodology.

“It has also been observed that the information about total Indian production is not readily available in the public domain and the applicant has devised a methodology to estimate the total Indian production and the share of the applicant alone and with the supporter in such estimated total Indian production. It has relied upon production data of Prime Movers to

which Trailers are attached wherein the subject goods are used which is published by the Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM) as a basis to derive the requirement of subject goods in India and to back calculate the probable domestic production in India. SIAM data has been made available for the entire POI. Out of the total number of productions of prime movers reported by SIAM, the applicant has considered about 10% as having requirement of 1 Axle in it and considered 80% as requiring 2 Axles and the remaining 10% having a requirement of 3 Axles. The number of Prime Movers considered for the POI involved various types of Trailers such as 35 Ton, 40 Ton etc... ..”

E. ASSESSMENT OF DUMPING – METHODOLOGY AN DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

E.1. Determination of Normal Value, Export Price and Dumping Margin

E.1.1. Normal Value of PUI

27. As noted herein above, the PUI is nothing but imports of PUC in CKD/SKD condition. In such a scenario determination of dumping margin has been carried out for both PUI and PUC. None of the exporters from China PR have responded to the present initiation and the Authority is constrained to adopt best available information for the determination of Normal Value. Accordingly, the normal value is determined on the basis of estimates of cost of production in India, duly adjusted to include selling, general & administrative costs of the domestic industry by adding reasonable profits. The normal value so determined for PUI and PUC for China PR provided in the table below;

28. Under Section 9A(1)(c) of the Act, normal value in relation to an article means:

- (i) *the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when destined for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
- (ii) *when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either*

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory to an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

Market Economy status for Chinese producers

29. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

“Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (“Anti-Dumping Agreement”) and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

“a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) *If the producers under investigation can clearly show that the conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;*

(ii) *The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.*

b) *In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.*

c) *The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.*

d) *Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."*

30. It is noted that while, the provisions contained in Article 15(a)(ii) have expired on 11.12.2016, the provisions under Article 2.2.1.1 of the WTO read with obligation under 15 (a) (i) of the Accession protocols require criterion stipulated in para 8 of the Annexure I of the India's Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the market economy status. It is noted that since the producers/ exporters from China PR have not responded and submitted response to the supplementary questionnaire in the form and manner prescribed, the normal value computation is required to be done as per provisions of para 7 of Annexure I of the Rules.

31. Accordingly, the normal value for all the producers/exporters from the subject country have been determined in accordance with para 7 of Annexure I of the Rules which reads as under.

In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.

32. The Authority notes that Normal Value for a country considered as a non-market economy is required to be computed in accordance with para 7 and 8 of Annexure-I of AD rules. In the instant

case, none of the exporters have responded and filed any Exporter questionnaire response and therefore the Authority notes that options under para 7 of Annexure-I to AD rules need to be explored.

33. Para 7 lays down a hierarchy for determination of normal value and provides that normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. Thus, the Authority notes that the normal value is required to be determined having regard to the various sequential alternatives provided under Annexure 7.
34. The domestic industry has claimed normal value on constructed basis by adopting the cost of the domestic industry for the purpose of determining dumping margin for PUI and also PUC. As an alternative basis, normal value based on import of PUI into India from other countries has also been proposed. It is noted in this regard that there was no significant import of PUI from other countries and import information is available only for a few components. Even the domestic industry did not provide any information on price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India.
35. The Authority has taken note of the arguments of various interested parties and notes that there is no sufficient information provided by any interested party to consider application of the first proviso of para 7 nor any information is available with the Authority for the same.
36. As regards the next proviso in para 7, the Authority notes from the import information as per DGCI&S data that the imports from countries other than China PR during the POI were only negligible and the import is not available for all the components. Imports of the subject products were primarily from China PR only. The Authority also notes that there is no reliable information available on the price from a third country to other countries based on exports of subject goods from such a third country. Therefore, in absence of sufficient information on export of PUC to other country, the Authority cannot adopt option 3 of para 7 hierarchy.
37. The Authority, therefore, has considered the constructed normal value on the basis of Indian cost of production (COP) with appropriate modifications as the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted to include a reasonable profit margin.
38. As regards to the hierarchy to be followed while determining normal value, the Authority has followed the following steps:
 - a) Neither the PUC nor the PUI has any dedicated customs classification. Hence, constructed normal value could not be derived based on exports from market economy third country by considering export data for any HS Codes. The same was also not possible as none of the interested parties in the current investigation has filed any data for the same.
 - b) Prices of PUI from third country to other country including India was examined and it was found that out of about 7 PUI types identified, imports were seen only for about 3 types and no imports were seen considering the remaining 4 types involved in PUI during the POI. Further, about 20% of such import was covered by a particular type of PUI from the other country and remaining 2 types constituted less than 0.25% of total imports. Reliance on such insignificant volume can result in distorting determination and cannot be used as a basis for normal value.
 - c) Since the initial two options cannot be adopted for want of reliable information, the Authority is bound to opt for the 3rd option that is price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin.

A.1.1 E.1.2. Export Price of PUI

39. As noted herein above, the PUI is nothing but imports of PUC in CKD/SKD condition. In such a scenario determination of dumping margin has been carried out for both PUI and PUC. None of the exporters from China PR have filed the Response and provided any information/details of export price. The Authority has, therefore, determined the export price on the basis of the DGCI&S import

data. The net export prices at ex-factory level in respect of all exporters from China PR is determined after making due adjustments for Ocean Freight, Insurance, Commission, Bank Charges, Insurance, Port Expenses and Inland Freight Charges on the basis of facts available to determine export price at ex-factory level. The net export price so determined for PUI and PUC is provided table below. The Normal Value (NV) is the value of average purchase and consumption price of PUI during POI.

40. Based on the above the dumping margin calculated for POI is tabulated as below.

PUI	Volume (KG)	Net Export Price (Rs/KG)	NV (Rs./KG)	Dumping Margin (Rs/KG)	Dumping Margin-% Range
Beam	31,048	86.75	***	***	(10)-0
Break Drum	1,83,845	64.61	***	***	0-10
Brake Shoe	7,16,206	93.70	***	***	20-30
Brake Spider	60,272	170.59	***	***	10-20
Camshaft	2,83,486	99.18	***	***	20-30
Hub	81,767	51.79	***	***	60-70
Slack adjuster	3,35,934	89.81	***	***	10-20
Weighted average	16,92,558	91.27	***	***	15-25

41. Further, the Authority has initiated Sunset review investigation vide F. No. 7/7/2021-DGTR, Case No. AD(SSR)-7/2021 dt. 19.04.2021 for the PUC. Since the PUC is being manufactured from the assembly of PUI involving a value addition, therefore the Authority has taken CNV of the PUC and arrived at the CNV of the PUI by deducting a value addition of ***% and compared it with net export price of PUI as an alternative method of normal value. The same is tabulated below.

CNV in SSR	Rs./KG	***
Add increase on account of RM cost during POI @ ***%	Rs./KG	***
Total Cost	Rs./KG	***
Less Value addition ***%	Rs./KG	***
CNV for PUI	Rs./KG	***
NEP for PUI	Rs./KG	91.27
Dumping Margin	Rs./KG	***
Dumping Margin	% Range	10-15

42. It can be seen that based on this methodology the dumping margin for PUI is also above de-minimis. Thus, by applying both the methodologies, it is seen that the PUI is being dumped.

F. ASSESSMENT OF CIRCUMVENTION AND ITS EFFECTS, IF ANY

F.1. EVIDENCE OF CIRCUMVENTION

A.2 F.1.1 Views of the Domestic Industry

43. The following submissions were made by the domestic industry:

- York fully supports the present anti-circumvention initiation initiated by the Authority based on inputs from Commissioner of Customs (Imports) Nhava Sheva.

- ii. The present investigation needs to be seen also in the back drop that an application for anti-circumvention investigation was filed on 12.10.2017 by York which was closed by the Authority on 10.04.2018 for want of further evidences. But the circumvention practices have become extremely rampant concerning the subject ADD over the years that the competent authorities themselves have started to take notice of such practices.
- iii. PUC and PUI are well defined in the initiation and the facts of the case make it evident that PUI is nothing but mere imports of PUC in CKD/SKD condition.
- iv. Axle for Trailers are getting imported in CKD (complete knock down)/SKD (semi knock down) condition by declaring it as parts of trailer axles with an intention to avoid ADD on 'Axle for Trailers' and the definition of PUI adopted fully reflects such practices being followed by some importers. The definition of PUC and PUI makes it evident that imports of PUI warrants ADD applicable at the time of imports of 'Axle for Trailers' to be extended to such imports of PUI and we pray for the same.
- v. PUI are nothing but PUC in CKD/SKD condition. Such imports have no other justification other than evasion of ADD on PUC. PUI thereafter is assembled as PUC with very minimal value addition that the circumvention is very evident.
- vi. The facts of the present case fulfil the requirements of an anti-circumvention investigation to warrant extension of ADD on PUC to PUI.
- vii. The facts as below will show that the present case meets all the requirements under the AC Rule;
 - a) the operation started or increased after, or just prior to, the anti-dumping investigations and the parts and components are imported from the country of origin or country of export notified for purposes of levy of anti-dumping duty.
 - b) the value added to the inputs brought in, during the assembly or completion operation, is less than 35% of the manufacturing cost.
 - c) the imports of PUI which is nothing but PUC in CKD/SKD condition continues to be at dumped rates
 - d) the import of PUI by evading the duty has undermined the remedial effect of ADD imposed on PUC.
 - e) the imports of PUI was intended only to circumvent the duty in force
- viii. Certain importers have started the practice of importing PUI instead of PUC to avoid ADD following the previous ADD investigation which is evident in the trend of imports of PUC and PUI as per DGCI&S which is as follows;

Year	PUC		PUI	
	Quantity (kg)	Trend	Quantity (kg)	Trend
2016-17	43,96,135	100	15,67,164	100
2017-18	34,26,319	78	36,46,430	233
2018-19	43,51,635	99	52,94,573	338
2019-20	22,27,747	51	25,58,862	163

- ix. The imports as per DGCI&S show that while the imports of PUC declined from 4396135KG to 2227747KG, the imports of PUI increased from 1567164KG to 2558862KG which is a substantial increase and indicates a clear shift in imports from PUC to PUI. The increase in imports of PUI is very notable in the period after levy of ADD on 29.11.2016.
- x. Details of imports as per IQR of HD Trailers Pvt Ltd shows that the imports of PUI which was 12963KG in the year 2015-16, which is prior to ADD, has increased to 342914KG in the

POI which alone shows the shift in imports from PUC to PUI. As per the importer, imports of PUC by them have been Nil in the corresponding period.

- xi. The facts show that the operation started or increased after, or just prior to, the anti-dumping investigations and the parts and components are imported from the country of origin or country of export notified for purposes of levy of anti-dumping duty instead of PUC only with an intention to avoid the applicable ADD.
- xii. The value addition on PUI to make PUC after importation of PUI will not be more than 15-20% which is much below the value addition requirement stipulated in the Rule which mandates a minimum value addition of 35%. Major importer like HD Trailers has been importing all major parts from China PR and in that case the value addition cannot be more than 35% in any case.
- xiii. HD Trailers have stated in their IQR that their “activity is to assemble PUI imported along with local material to produce the PUC” and it was further submitted that they import Axle Beam/Tube, Cam Shaft, Cam Set, Slack Adjuster and Hub Cap. What is important to be noted here is that Axle Beam/Tube consists of significant share of the raw material cost and also overall cost of the PUC and if such substantial part has been getting imported, then the chances of value addition of 35% in such assemblage is almost impossible practically.
- xiv. York does not have access to any actual data of value addition by the importers. The response filed by HD Trailers appears grossly deficient and will not permit any determination of cost of PUC and also value addition details from PUI to PUC unless the party substantiates their response with all the details. We request the Authority to direct HD Trailers to share cost of production details for the POI along with complete details of parts imported and domestically procured to determine the cost of production of PUC and also value addition done by the Company from PUI stage to PUC stage.
- xv. The imports of PUC continued to undercut the price of domestic industry and such price effects are caused by imports of PUC in CKD/SKD condition.
- xvi. The market share of import of PUC remained very high in the POI as the PUC in in CKD/SKD condition i.e. the PUI continued to reach India. The increase in import of PUI signifies the fact that reduction in import of PUC did not help the DI to increase its market share as the PUC continued to reach India in CKD/SKD condition without any ADD. Thus, market share of the domestic industry was impacted.
- xvii. As a result of import of PUC in CKD/SKD condition, the sales, production and capacity utilization of the domestic industry once again declined during the POI after some improvements between 2016-17 and 2018-19.
- xviii. Even the price parameters of the domestic industry shows adverse situation created by imports of PUI. The profitability of the DI which has turned positive in 2017-18 from negative levels in the period 2016-17 once again become negative in the POI.
- xix. Similar is the case of ROCE. ROCE which improved between 2016-17 and 2018-19 drastically fell in the POI to negligible levels in the POI and was in the range of 0-5%.
- xx. The overall situation of the DI shows material injury in the POI and the cause of such injury is imports of PUC in CKD/SKD condition and the situation can be corrected by extending the duties applicable on PUC to the PUI also which is nothing but PUC is CKD/SKD condition.
- xxi. H.D. Trailers had contended that they should be informed of how York accessed a letter concerning circumvention practices from Department of Revenue Intelligence (DRI). The intended insinuation of the Company is baseless and the letter submitted would show that the letter has been in normal course only.
- xxii. The contentions of HD Trailers on the actions of Customs Commissioner are not of any merit. The Customs Commissioner rightly doubted circumvention and the claims to the contrary are self-serving.

- xxiii. The request for copy of the letter from Customs Commissioner raised by HD Trailers has no legal sanctity. Rule 26 shows that the Authority is not bound to share the details forming the basis of *suo motu* initiation with the interested parties and it is only that the parties may be allowed to provide information as per Rule 6 upon initiation. Thus, the Authority is not legally bound to share the information received from Customs Commissioner with the parties.
- xxiv. There is no basis for HD Trailers to say DRI letter submitted by York be given to other party or removed from records. The letter was received through proper means and should be considered as part of the records. The HD Trailer is apparently a company engaged in many practices of evasion of duties and they cannot get scot free by interpreting the law in their favour without any proper understanding of the same.
- xxv. The submissions of HD Trailers that the permission for DGCI&S data prior to 1.1.2018 is not granted is only an alibi as it appears. The company has not collected and submitted any analysis for any period if they are serious about procuring DGCI&S data.
- xxvi. The contention that requirement of dumping and injury is not met is a statement made without any basis by HD Trailers. Dumping and injury is not *pari materia* in circumvention matter and requirement of a fresh case and circumvention is totally different.
- xxvii. It is a baseless statement made by HD Trailers that York has imported from China PR. It has been submitted that the company or its related party did not import from China PR or any of its related party in China PR export the subject goods to India.
- xxviii. The claim of York on pricing of PUI is incorrect and is without any basis. PUC is imported as PUI to evade the duties.
- xxix. The contention that York's data concerning material handling and financial aspects are contradicting each other and requires forensic audit is a baseless contention. The audited financial reports are amenable to verification by the Authority as per rule and York has no objections to any such verification.

A.3 F.1.2. Views of the Opposing Interested Parties

44. The opposing interested parties have made the submissions as under:

- i. H.D Trailers Pvt Ltd submitted that their activity is to assemble PUI imported along with local materials to produce PUC.
- ii. M/s H.D. Trailers Pvt. Ltd. has established its factory for the manufacture of trailer axles much earlier to the imposition of ADD on trailer axles and now around 70% of the components of the trailer axle are indigenous.
- iii. HD Trailers are not importing all the parts such as drums, brake shoe assembly etc.
- iv. The cost sheet furnished by H.D Trailers Pvt Ltd would show value addition of more than 69% which is much higher than the threshold of 35% provided in the Rule.
- v. The value addition has to be arrived at by deducting the cost of imported raw materials from the cost of the assembled, complete or finished article.
- vi. The axle beam tube is a vital part for the axle. The tube used by the rest of the manufacturers is consisting of more than one part joined by welding. The tube imported are seamless and thus have more strength. None of the Indian producers make seamless tube. Likewise the hub cap imported is a superior product.
- vii. H.D Trailers Pvt. Ltd. should be considered as domestic producer and not importer as the value addition is more than 69%.
- viii. HD Trailers Pvt. Ltd. requested for permission to access the import data from DGCI&S from 01.04.2015 to till date. The said data is available with DGCI&S only up to September 2020. But DGTR permitted the aforesaid company to access the import data from January 2018 only. Hence, M/s HD Trailers Pvt. Ltd. could not access the part of the necessary data which it required.

- ix. The initiation notification of the DGTR dt. 15.09.2020 referred to the information received from Commissioner of Customs (Imports), Nhava Sheva as the basis for investigation. The request of the company for being provided with a copy of the said letter could not get any response.
- x. M/s. H.D. Trailers Pvt. Ltd. contested that York had access to the letter from DRI. However, its request to DGTR in this regard failed to evoke a reply.
- xi. Two of the prime requirements for initiation of the investigation are the dumping and the injury which is not met in the present matter as can be seen from the submissions of York.
- xii. As to the letter of the Commissioner of customs, Nhava Sheva, had they analysed the issue in the right perspective, they themselves could have found that the imports by M/s HD Trailers Pvt. Ltd are adding up to only 31% of the cost of an axle and thus there is no question of circumvention. Had these facts been taken up for consideration, the situation would not have resulted in the initiation of the present investigation.
- xiii. Commissioner of Customs, Nhava Sheva ought to have realised that HD Trailers Pvt Ltd is not circumventing but the imports are well beyond the limits prescribed for consider the circumvention criteria.
- xiv. M/s. H.D. Trailers Pvt. Ltd.'s requests for supply of the letter of the Commissioner of Customs, Nhava Sheva has not been acceded to. Hence, the company is deprived of making an effective representation vis-a-vis the justification for the initiation of the inquiry.
- xv. Either the letter of the DRI should have been furnished to M/s H.D. Trailers Pvt. Ltd. or the same should be deleted from the material to be considered in the investigation.
- xvi. The company's request for supply of import data from 1.4.2015 has been truncated and only data from 1.1.2018 was permitted. Thus, it was prevented from analysing the import data for the relevant periods.
- xvii. M/s. York has made incorrect submissions. York has imported from China PR during the relevant period and the same can be verified by calling the data from DGCI&S.
- xviii. York's submissions about the pricing of PUI are incorrect and not supported by any evidence. At least they could have furnished their cost data to establish their doubts.
- xix. York's data when it comes to the material handling and the financial aspects are contradicting each other. Thus, a forensic audit is necessary to see whether their declarations are correct.
- xx. HD Trailers Pvt Ltd had 69% of the parts domestically hence the company should be treated as DI. None of the Indian producers make seamless tube hence it is imported.

A.4 F.2. Examination by the Authority

45. The Authority notes the submissions made by various interested parties and the relevant provision of the Act/Rules as under:

Section 9A(1A) of the Customs Tariff Act-

Where the Central Government, on such inquiry as it may consider necessary, is of the opinion that circumvention of anti-dumping duty imposed under sub-section (1) has taken place, either by altering the description or name or composition of the article subject to such anti- dumping duty or by import of such article in an unassembled or disassembled form or by changing the country of its origin or export or in any other manner, whereby the anti-dumping duty so imposed is rendered ineffective, it may extend the anti-dumping duty to such article or an article originating in or exported from such country, as the case may be."

Rule 25 of AD Rules-

"25. Circumvention of anti-dumping duty.- (1) Circumvention shall be considered as a change in the pattern of trade between any country and India or between individual companies in any country subject to measures and India, as a result of a practice, process or

work for which there is insufficient cause or economic justification other than the imposition of the duty; and where there is evidence of injury or that the remedial effects of the duty are being undermined in terms of the prices or quantities or both of the like product; and where there is evidence of dumping in relation to the normal values previously established for the like product, if necessary with appropriate changes or adjustments or in accordance with the provisions of rule 10.

(2) The practice, process or work referred to in the sub-rule (1) includes, inter alia,-

(a) where an article subject to anti-dumping duty is imported into India from any country including the country of origin or country of export notified for the purposes of levy of anti-dumping duty, in an unassembled, unfinished or incomplete form and is assembled, finished or completed in India or in any other country, such assembly, finishing or completion shall be considered to circumvent the anti-dumping duty in force if, -

(i) the operation started or increased after, or just prior to, the anti-dumping investigations and the parts and components are imported from the country of origin or country of export notified for purposes of levy of anti-dumping duty;

and

(ii) the value added to the inputs brought in, during the assembly or completion operation, is less than 35% of the manufacturing cost:

Provided that for calculation of value addition, expenses on account of procurement of technology, such as patents, copyright, trademark, royalty, technical know-how, consultancy charges, etc., shall not be included in the value of the parts brought in.

Explanation I. - *'Value' means the cost of assembled, complete or finished article less value of imported parts or components.*

Explanation II. - *For the purposes of calculating the 'value', expenses on account of payments relating to intellectual property rights, royalty, technical know-how fees and consultancy charges, shall not be taken into account.*

(b) where an article subject to anti-dumping duty is imported into India from country of origin or country of export notified for the levy of anti-dumping duty after being subjected to any process involving alteration of the description, name or composition of an article, such alteration shall be considered to circumvent the anti-dumping duty in force if the alteration of the description or name or composition of the article subject to anti-dumping duty results in the article being altered in form or appearance even in minor forms regardless of the variation of tariff classification, if any;

(c) where an article subject to anti-dumping duty imported into India through any exporter or producer or country not subject to anti-dumping duty, such exports shall be considered to circumvent the anti-dumping duty in force if the exporters or producers notified for the levy of anti-dumping duty change their trade practice, pattern of trade or channels of sales of the article in order to have their products exported to India through any exporter or producer or country not subject to anti-dumping duty;

(d) any other manner whereby the anti-dumping duty so imposed is rendered ineffective

46. For the purposes of examination of imports of both PUC and PUI, the Authority has considered transaction wise import data as provided by DGCI&S. With respect to allegation of circumvention of duties imposed on PUC by importing PUC in CKD/SKD condition as PUI, the Authority has examined specifically the said form of circumvention in this investigation.

47. The Authority notes that the producers/exporters or exporters from China PR have not filed any questionnaire response in this matter. The Authority further notes that the AD measure is producer/exporter specific and in an Anti-Circumvention investigation, producers/exporters subjected to an AD investigation need to provide data so that the shift in trade pattern specifically by them post levy of a measure can be evaluated. Also, the value addition related to conversion of

PUI to PUC is also computed. The Authority notes that none of the producers/exporters from China PR has responded in the present investigation as mentioned in the foregoing paras.

48. The contentions of the interested parties are *ipso facto* addressed at relevant portions in these final findings and hence the same are not being addressed separately. However, with regard to the contention of HD Trailers Pvt. Ltd. that the information received from Commissioner of Customs, Nhava Sheva which formed the basis of current initiation is not shared with them, the Authority notes that the obligation of the Authority under the Anti-Dumping Rules initiating an investigation is to equip the interested parties with necessary information so as to enable them to have a fair and reasonable opportunity to file their submissions and protect their interest and due cognizance has been taken by Initiation notice which contained the specific details forming the basis of the present investigation and all the interested parties were given the opportunities to provide their views and evidences as required under the Rule. It has been contended by HD Trailers that the case does not meet the conditions of dumping and injury. However, it is noted that such a requirement is not a part of anti-circumvention investigation. In addition, it is also noted that M/s HD Trailers have been granted necessary permissions to procure the DGCI&S data for better appreciation of the imports of PUI forming prime consideration on the conclusions of the current case.
49. Further, one of the importers of the PUI in India namely H.D Trailers Pvt Ltd have filed some information and it is noted that the information provided the company is grossly deficient and cannot be relied upon to determine the cost of finished goods and also value addition from PUI to PUC stage.
50. In view of the absence of cooperation from producers/exporters/importers, the Authority considered the trade pattern shift and the value addition in converting PUI to PUC on the basis of best available information. While import data procured from DGCI&S have been used for trade pattern shift, data provided by the cooperating domestic producer of subject goods have been used for purposes including value addition from PUI to PUC. The Authority has examined the stipulated criteria on shift in trade pattern, value addition threshold of PUI to PUC, whether change in trade pattern is stemming from an economic justification or is on account of circumvention to effect the levy of ADD, in accordance with Rule 25(1).

F.2.1 Change in Pattern of Trade

51. The Authority has examined the stipulated criteria on shift in trade pattern to PUI from PUC, whether change in trade pattern is stemmed from an economic justification or is on account of circumvention to effect the levy of ADD, in accordance with Rule 25(1).
52. The change in pattern of trade has been analysed from 2016-17 to the POI, by analysing the volume of imports of the PUC and PUI. The trend of import of PUC and PUI is noted as follows as per the DGCI&S data;

Year	PUC		PUI	
	Quantity (MT)	Trend	Quantity (MT)	Trend
2016-17	4,396	100	1,527	100
2017-18	3,426	78	3,513	230
2018-19	4,352	99	5,007	328
2019-20	2,228	51	1,779	117

53. It is noted that imports of the PUC from China PR declined from 4396 MT in the base year to 2228 MT by the POI whereas the imports of PUI which was 1527MT in the base year increased to 1779 MT in the POI which is a substantial increase even though there was a decline in imports of PUI during the POI viz. the immediate previous year.
54. Thus, it is noted that there is a change in the pattern of trade of PUC from China PR post levy of Anti-dumping duties.

F.2.2 Shift in Trade Pattern

55. Imports of PUC and PUI have been considered based on the transaction wise import data provided by DGCI&S. It is very apparent from the import data concerning PUC and PUI that imports of PUI commenced or increased after imposition of ADD on PUC. In the present case, ADD on PUC have been in effect from 2016 and the imports of PUI commenced or increased thereafter confirming shift in trade pattern. Coincided with an increase in import of PUI, there has been a fall in import of PUC.

	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
Imports from China - PUC (MT)	4,917	4,433	3,066	6,600	6,300	4,371	3,426	4,352	2,228
Imports from China -PUI (MT)	-	-	-	-	-	1,527	3,513	5,007	1,779
Total Imports PUC&PUI-MT	4,917	4,433	3,066	6,600	6,300	5,898	6,939	9,358	4,007
Import PUC %	100	100	100	100	100	74	49	46	56
Import PUI%	-	-	-	-	-	26	51	54	44

Demand in India-MT	16,902	13,923	8,785	16,684	24,375	28,735	42,832	40,191	15,418
Sales of Domestic Industry-MT	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Sales of other Indian Producers-MT	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Sales of Indian producers-MT	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Market share of Indian producers-%	***	***	***	***	***	***	***	***	***
Market share of DI-%	***	***	***	***	***	***	***	***	***

56. It is seen that the imports of PUC alone were taking place till 2015-16 and the same started to decline after imposition of ADD in November, 2016. Similarly, imports of PUI which was NIL till 2015-16 commenced and started to increase post imposition of ADD on PUC. Consequently, market share of Indian producers as a whole which has been on an increasing trajectory and reached a level of 98.76% post imposition of ADD in the year 2016-17, once again started declining after commencement of imports of PUI and as a result market share of the Indian producers once again declined to a level of 74.01% during the POI.

F.2.3 Justification, Economic or Otherwise, Other than Imposition of Anti-Dumping Duty

57. The Authority notes that none of the producers/exporters from China PR have responded in the present investigation and the participating importers have also failed to provide appropriate information to establish any justification, economic or otherwise other than imposition of Anti-Dumping Duty to justify the shift in trade pattern from PUC to PUI.

58. It is also noted from the response of one of the importers namely H.D Trailers Pvt Ltd that they import parts of Axle for trailers as a business activity and the party contended that majority of their production of subject goods now comprises parts produced domestically. As noted, the PUI in the present matter is PUC in CKD/SKD condition. The PUI is assembled into the PUC after imports and in the process the applicable ADD is apparently evaded. It is seen from the information on record that PUI, which is part of Axle for Trailers in CKD/SKD condition, as such has no standalone application and has utility in the production of PUC only. Therefore, it is seen that the assembly of PUI into PUC is not any substantial production activity and it is noted that the production activity undertaken to assemble the PUI into PUC is minimal and incremental and below the value addition prescribed under Rule 25 of the AD Rules.

59. The domestic industry has provided information on gross investment, value addition from PUI to PUC, employment, sales value and raw material cost. As per the information provided, it is seen

that plant & equipment, production process & technology and manufacturing activities are majorly involved in the production of PUC and no such process is apparent in the mere assembly undertaken for converting PUI to PUC.

F.2.4. Value Addition

60. The Rule 25 of AD Rules requires that “the value added to the inputs brought in, during the assembly or completion operation, is less than 35% of the manufacturing cost”. Since, there is no meaningful cooperation from the exporters/importers, the value addition is determined based on the best available information.
61. M/s. H.D. Trailers Pvt. Ltd. participated in the current investigation and filed importers questionnaire response. They claimed that they do 69% value addition in India, however no data/ documents were filed by them to substantiate this contention. Authority vide letter dated 17th June 2021 requested the importer to file a cost sheet in the prescribed format with supporting documents. The importer filed the same vide their mail dated 29th June, 2021. On scrutiny of the same it was found that the data submitted by them was not reconciled with the Audit report for 2019-20 as submitted by them. Therefore, the Authority was bound to construct the value addition based on the facts available and using the audited annual report of the importer. Based on the same the value addition is tabulated as below.

Description	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
Cost of Raw material Consumed	Rs.Lakhs	***	***	***	***
Total Cost	Rs.Lakhs	***	***	***	***
Less RM Cost	Rs.Lakhs	***	***	***	***
Less Purchase of Trading goods	Rs.Lakhs	***	***	***	***
Less Change in stock	Rs.Lakhs	***	***	***	***
Value Addition	Rs.Lakhs	***	***	***	***
Dedicated Manufacturing Expenses		***	***	***	***
Depreciation	Rs.Lakhs	***	***	***	***
Other Direct Expenses	Rs.Lakhs	***	***	***	***
Repair & Maintenance	Rs.Lakhs	***	***	***	***
Total Dedicated Expenses for Manufacturing	Rs.Lakhs	***	***	***	***
Common Expenses	Rs.Lakhs	***	***	***	***
Share of Common Exp. To Manufacturing	Rs.Lakhs	***	***	***	***
Value addition for Manufacturing	Rs.Lakhs	***	***	***	***
Value addition %	% Range	15-25	10-20	10-20	15-25

62. It is seen that in none of the years under consideration, the value addition has been more than 25%.
63. The Authority notes that the change in pattern of trade seems to be aimed at evading the applicable ADD on PUC by importing PUC as PUI.

G. ASSESSMENT OF EFFECT OF CIRCUMVENTION ON EXISTING ANTI-DUMPING MEASURES AND DOMESTIC INDUSTRY.

64. The manner in and the extent to which the circumvented products are undermining the duty imposed and thereby rendering such duty as redundant is important to be analysed. The Authority has examined whether the remedial effects of anti-dumping duties have been undermined in terms of market share, price effects and adverse effects on key economic parameters due to impact of shift in trade by increased imports of PUI from the subject country.

G.1 Market share assessment and effects of circumvention on market share of the domestic industry

65. The Authority has examined market share of domestic industry and imports of PUC in the Indian demand and have seen the same in view of the imports of PUI;

Market Share in Demand	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Sales of Domestic Industry	MT	***	***	***	***
Sales of Other Indian Producers	MT	***	***	***	***
Imports from Subject Country-PUC	MT	4,396	3,426	4,325	2,228
Imports from Subject Country-PUI	MT	1,527	3,513	5,007	1,779
Demand	MT	28,735	42,832	40,191	15,418
Trend	Indexed	100	149	140	54
Sales of Domestic Industry	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	117	140	177
Other Indian Producers	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	97	62	26
Imports from Subject Country-PUC	%	15.30	8.00	10.76	14.45
Trend	%	100	52	70	94
Imports from Subject Country-PUI	MT	5.31	8.20	12.46	11.54
Trend	Indexed	100	154	234	217

66. It is noted that the demand as determined includes both PUC and the volume of imports of PUI. It is further noted that market share of both domestic industry and China PR have increased in the POI. As noted earlier, PUI is used in the production of PUC only and it does not have any standalone usage. It is noted from the above Table that while the share of PUC remained at similar levels, the share of imports of PUI kept on increasing over the injury period which prevented further increase in the market share of the domestic industry.

G.2 Effect of circumvention on Net Sales Realization of the DI during the POI

67. With regard to the effect of imports of PUI on prices, it is required to be analysed whether there has been a significant price undercutting by the circumvented imports as compared to the price of the like products in India. The Authority considers the same as under.

Price Undercutting	Unit	2016-17	2017-18	2018-19	POI
Import volume of PUC	MT	4,396	3,426	4,352	2,228
Import volume of PUI	MT	1567.16	3646.43	5294.57	2558.86

Landed price of imports of PUC	Rs/Kg	109.46	113.09	126.01	121.28
Net Sales Realization (NSR)	Rs/Kg	***	***	***	***
Price undercutting	Rs/Kg	***	***	***	***
Price undercutting	%	***	***	***	***
Price undercutting	% Range	20-30	10-20	0-5	5-15

68. Since the landed price of imports of PUI cannot be directly compared with the NSR of subject goods, the landed price of PUC is compared with NSR of the subject goods. It is seen that imports of PUC have been undercutting the NSR of the domestic industry throughout the injury period and the undercutting increased during the POI over the immediate previous year. Landed price of imports of PUC being below the selling price of the domestic industry signifies the situation that imports of PUI have also been at undercutting levels as the PUI is nothing but imports of PUC in CKD/SKD condition.

69. The Authority holds that the above price undercutting of PUC through circumvention phenomena has in fact adversely impacted the pricing of the domestic industry.

Landed Price of PUC and PUI and Price effects

70. Landed price of PUC and PUI have been worked out based on transaction wise import data as provided by DGCI&S. The table below shows the calculation of landed value.

Particulars	Unit	PUC	PUI
Landed Value	Rs./KG	#132.74	122.51
Net Sales of Realisation of the domestic Industry	Rs./KG	***	***
Price Undercutting	Rs./KG	***	***
Price Undercutting	%	***	***
Price Undercutting	% Range	0-5	5-10

Landed value of PUC includes anti-dumping duty in force.

71. PUC landed in India after payment of applicable anti-dumping duties, whereas PUI were imported without any anti-dumping duties. It can be noted that while PUC landed in India at a price of Rs. 132.74/- per Kg, PUI landed in India at a price of Rs. 98.79/ Kg and considering a value addition thereafter of about **%, the landed price of assembled PUI remained at Rs.122.51/Kg. Such difference in landed price of PUC and PUI shows the effect of evasion of anti-dumping duties and circumvention of applicable anti-dumping duties is evident due to such price differences. Further, such activities by the importers have undermined the efficacy of the ADD measures.

H. POST DISCLOSURE COMMENTS

72. Following submissions have been made by the domestic industry:

- The facts as disclosed clearly show that the PUI which have been getting imported from China PR are nothing but imports of 'Axle for Trailers' in CKD/SKD condition by declaring it as 'parts of trailer axles'. The Authority may confirm its observations on the PUC and the PUI in the final finding.
- Only York have come forward and cooperated with the Authority in this matter as a producer of subject goods. York clearly satisfies standing requirements as it hold a major proportion in the total Indian production and York should please be confirmed as the eligible domestic industry concerning this investigation in the final finding.

- c) The facts as disclosed proves that there was a notable shift in the pattern of trade from the import of the PUC to the PUI and such shift was to circumvent the duties and there are no economic justifications for such shifts other than evasion of applicable duties.
- d) The facts of the present case make it evident that ADD on the PUC is being circumvented by importing the same in CKD/SKD condition defined as the PUI and it is just and fair that duties on the PUC is made applicable on imports of the PUI also.
- e) It is very evident that the process of circumvention started or intensified after the imposition of ADD to evade such duties and as a result of the circumvention, the remedial effects of the duties are highly undermined in this matter. The circumvention clearly prevented more gain in market share by the domestic industry and landed price of such imports at undercutting levels prevented fair price increases by the domestic industry which would have taken place otherwise.
- f) The facts as disclosed clearly show that the value addition has been much lower than the statutory threshold of 35% and it is also clear that the imports of the PUI were taking place at dumped levels. The circumventing imports were undercutting the price of the domestic industry to significant levels that the price injury created by the circumvention is clear.
- g) The benefit of duties in force were clearly undermined as the dumped and circumvented material reached India at a price below the NSR of the domestic industry even after including the applicable ADD in force.
- h) It is evident from the factual disclosure that M/s HD Trailers Pvt Ltd have clearly failed to cooperate with the Authority meaningfully and the party merely resorted to making unsubstantiated claims. The facts clearly show that HD Trailers Pvt Ltd could not prove its claims with supporting evidences and we request the Authority to consider best available information for the purpose of final finding also by rejecting the unsubstantiated claims of the said importer wherever warranted.
- i) It is clear from the facts that the case meets all the requirements to recommend for circumvention duty since a) the product under investigation started or increased after, or just prior to, the anti-dumping investigation and the parts and components are imported from the country of origin or the country of export notified for purposes of levy of anti-dumping duty, b) the value added to the inputs brought in, during the assembly or completion operation, is less than 35% of the manufacturing cost, c) the imports of the PUI which is nothing but the PUC in CKD/SKD condition continues to be at dumped rates, d) the import of the PUI by evading the duty has undermined the remedial effect of ADD imposed on the PUC and e) the imports of the PUI was intended only to circumvent the duty in force.
- j) In view of the facts as disclosed, which demonstrates circumvention and its adverse effects on the domestic industry, the Authority may recommend for extension of ADD on the PUC also onto imports of the PUI from China PR.

73. Following submissions have been made by M/s H.D. Trailers Pvt Ltd.

- a) The submissions of M/s H.D. Trailers Pvt Ltd asking for specific investigation as well as consideration have not been looked into. The details and the documents requisitioned by M/s H.D. Trailers Pvt Ltd have been denied and thus effectively blocking it from making a true and effective representation of the case. However, averments of M/s York Transport Equipment have been taken without any proof.
- b) The forensic audit requested for the books of York has not been taken into consideration. It has been pointed out that the books of York are manipulated. Also, the imports by York and its related parties have not been investigated.
- c) The formula adopted for ascertaining the production and the consumption of axle by York is faulty.

- d) York is adopting manufacturing activity which is similar to what H D Trailers Pvt Ltd has been adopting.
- e) As to the alleged variations from work sheet and the balance sheet figures of M/s H.D. Trailers Pvt Ltd, the confusion is solely due to the failure on Authority's part in understanding the nature of the activities of the company. The Authority appears to have proceeded with the facts without asking clarification.
- f) M/s H.D. Trailers Pvt Ltd not only manufactures trailer axle but is also manufacturing suspension, which is totally away from the scope of ADD. Likewise, the goods imported are not just the PUC and the PUI but include parts of the suspension. The confusion arose because the Authority have taken manufacturing details given in the balance sheet as that of Trailer axle and the import figures as the import of only the PUI.
- g) As regards the issue of value addition, the 'value' as given in clause (ii) in Rule 26 defines the value as the cost of assembled or finished article less value of imported parts or components. Thus, this rule stipulates the consideration of cost of assembled, complete or finished article and the value of the imported parts or components.
- h) In case of M/s H.D. Trailers Pvt Ltd, the value addition to the imported goods has to be considered as the difference between the total cost of the assembled article and that of the cost of the imported goods, which works out to Rs. 859.00 lakhs (difference between 1855.87 and 996.87). Thus, the amount of Rs. 859.00 lakhs when taken as a % of the cost of imported components works out to be 86.17% which is far above the threshold of 35%. Hence the question of circumvention does not arise.
- i) The issue in hand is whether there is circumvention of the anti-dumping duty imposed on trailer axles imported into India and the examination should not be narrowed down to M/s H.D. Trailers Pvt Ltd. only.

EXAMINATION OF THE AUTHORITY

74. The Authority notes that most of the submissions made by the domestic industry and the other interested party are repetitive in nature. These submissions have already been examined at appropriate places in these final findings. Further, the Authority has examined additional/new relevant submissions of all the interested parties as under:
- a) With regard to the contentions of M/s H.D. Trailers Pvt. Ltd. that their submissions were not considered and requisitioned documents by them were not provided, the Authority notes that the contentions have no merit. The Authority have considered and addressed all submissions supported with evidence as required under the Rules and contentions not supported by facts or law alone have been rejected. Interested parties have been asked to exchange the non-confidential version of their submissions with the other interested parties and in view of the same, the contention that the Authority has denied access to documents is also rejected.
 - b) The Authority notes that while York was found to be the domestic industry in the original investigation, M/s H.D. Trailers Pvt. Ltd. registered itself as an importer of the PUC and filed an importer questionnaire response. However, in the present anti-circumvention case, M/s H.D. Trailers Pvt. Ltd. has contested that it is carrying out the manufacturing activity similar to what York, which is the domestic industry in the present case, is adopting for the production of PUC.
 - c) In view of the comments received from the interested parties, the Authority carried out a discussion cum verification of M/s H.D. Trailers Pvt. Ltd. through Digital Video conferencing in the wake of COVID-19 in order to understand the contentions made and the manufacturing process being undertaken by it. It emerged from the discussions that the nature of activity carried out by M/s H.D. Trailers Pvt. Ltd. during the POI is more of an importer though in the ongoing sunset review of the existing anti-dumping duties on the imports of PUC, the company has claimed itself to be a producer/manufacturer. Despite

several submissions the party could not place on record any conclusive evidence to establish themselves as manufacturers of the PUC during the period of investigation. It is further noted that the legal representative of the company also admitted that the company is gradually shifting towards manufacturing activity which is beyond the scope of this anti-circumvention investigation. In view of the above, the contention of M/s H.D. Trailers Pvt. Ltd. that the manufacturing activity carried out by them is similar to York cannot be accepted.

- d) With regard to the contention that forensic audit of the books of York has not been taken into consideration, the Authority notes that the submissions made, and documents submitted by the domestic industry and the other opposing parties have been taken into consideration only after due examination and verification as per the practices followed by the Authority. Further, the scope of the investigation is to establish whether circumvention has taken place to undermine the efficacy of existing anti-dumping duties.
- e) With regard to the contention that the formula adopted for ascertaining the total Indian production of axle by York is faulty, the Authority notes that the formula adopted in the present investigation to calculate the total axle requirement based on SIAM data pertaining to the production of Prime Movers was found reasonable and adopted even in the original investigation. There are no evidences adduced by the opposing party to show that such formula is totally irrational. It is further noted that even if a formula of 80%*2.5 axles and 20%*3 axles is considered as a conservative approach, still York alone holds a major proportion of 76 % in the total Indian production based on the SIAM data relied upon by them. SIAM data *per se* is not disputed by the opposing parties.
- f) With regard to the contention of HD Trailers that the alleged variations in its work sheet and the balance sheet figures are due to the confusion of the Authority, it is noted that the requirements in various formats prescribed is very specific to help the parties to provide the relevant information in line with their audited books and the Authority has considered and analysed the information as submitted by the interested parties. Hence, the contention that the Authority getting confused with the information is not correct. The Authority appropriately considered the information pertaining to the PUI and others from the records submitted by the party.
- g) With regard to the contention of M/s HD Trailers Pvt. Ltd. that the calculation of value addition adopted in the disclosure statement is not correct either legally or factually, the Authority notes that how to calculate value addition in the context of an anti-circumvention investigation is explicitly provided in the Anti-Circumvention Rule and the same has been adopted by the Authority. Thus, the facts disclosed with regard to value addition in the disclosure statement reflected the correct legal position. The Authority has also examined the factual rebuttals by HD Trailers on the value addition calculation and notes that the facts disclosed earlier do not warrant any modifications as HD Trailers could not submit any new facts to justify the modifications in the earlier calculations.
- h) With regards to the contention of M/s HD Trailers Pvt. Ltd. that the examination of circumvention should not be narrowed down to only HD Trailers Pvt Ltd, the Authority notes that the outcome of the present anti-circumvention investigation would be applicable on all the circumventing imports of the PUC and not just restricted to any particular importer.
- i) With regard to the claims of the domestic industry, the Authority notes that the submissions are repetition of their earlier claims and therefore has not been addressed separately.

I. CONCLUSIONS

75. Having initiated the present investigation based on inputs from the Commissioner, Nhava Sheva and after examining the contentions of the domestic industry and the other interested parties and on the basis of the analysis as above, the Authority concludes as under:

- a) There has been a change in the pattern of trade in the case of import of the PUC and the PUI from China PR post imposition of Anti-dumping duties on the PUC.
- b) The value addition in converting the PUI (Axle for Trailers in Completely Knock Down/Semi Knock Down condition) into the PUC (Axle for Trailers) is significantly less than the prescribed threshold in the Anti-circumvention Rules.
- c) Imports of the PUI from China PR have been entering at dumped prices.
- d) The import of the PUI has undermined the remedial effects of existing Anti-dumping measure on PUC imposed vide Custom Notification No.54/2016-Customs (ADD) dated 29th November, 2016.

J.RECOMMENDATIONS

76. The Authority in view of the afore stated factual matrix;

- a) Recommends extension of the existing Anti-Dumping Duty on imports of Axle for Trailers, originating in or exported from China PR imposed by Central Government vide Notification No. 54/2016-Customs (ADD) dated 29th November, 2016 on import of the PUI also originating in or exported from China PR. (Duty tabulated in the Custom Notification No. 54/2016-Customs (ADD) dated 29th November, 2016 is enclosed at **Annexure-A**).
- b) The validity of Anti-dumping Duty on the PUI would be from the date of notification of the duty by Central Government and shall be co-terminus with the duty on Axle for Trailers originating in or exported from China PR.

K. FURTHER PROCEDURE

77. An appeal against the order of the Central Government arising out of this final finding shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975.

ANANT SWARUP, Designated Authority

Annexure-A

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th November, 2016

No. 54 /2016-Customs (ADD)

G.S.R. (E). -Whereas, in the matter of “Axle for Trailers” (hereinafter referred to as the ‘subject goods’), falling under tariff item 8716 90 10 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the ‘Customs Tariff Act’), originating in, or exported from People’s Republic of China, (hereinafter referred to as the ‘subject country’), and imported into India, the designated authority in its final findings published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, *vide* notification number 14/17/2015- DGAD, dated the 30th September, 2016, has come to the conclusion that -

- (a) the subject goods have been exported to India from the subject country below their associated normal values;
- (b) the domestic industry has suffered material injury;

(c) the material injury has been caused by the dumped imports of the subject goods from the subject country,

and has recommended imposition of definitive anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in, or exported from the subject country and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), exported by the exporters as specified in the corresponding entry in column (7), imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (8), in the currency as specified in the corresponding entry in column (10) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (9) of the said Table, namely :-

Table

S. No.	Tariff Item	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Exporter	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	8716 90 10	Axle for Trailers	People's Republic of China	People's Republic of China	Guangdong FUWA Engineering Manufacturing Co., Ltd.	Guangdong FUWA Engineering Manufacturing Co., Ltd.	0.16	Kg	United States Dollar
2.	8716 90 10	Axle for Trailers	People's Republic of China	People's Republic of China	Guangdong FUWA Heavy Industries Co. Ltd.	Guangdong FUWA Heavy Industries Co. Ltd.	0.16	Kg	United States Dollar
3.	8716 90 10	Axle for Trailers	People's Republic of China	People's Republic of China	Shandong Jinsheng Axle Manufacturing Co., Ltd.	Shandong Jinsheng Axle Manufacturing Co., Ltd.	0.14	Kg	United States Dollar
4.	8716 90 10	Axle for Trailers	People's Republic of China	People's Republic of China	Any combination other than Sl. No. 1 to 3 above		0.46	Kg	United States Dollar
5.	8716 90 10	Axle for Trailers	People's Republic of China	Any country other than People's Republic of China	Any	Any	0.46	Kg	United States Dollar
6.	8716 90 10	Axle for Trailers	Any country other than People's Republic of China	People's Republic of China	Any	Any	0.46	Kg	United States Dollar

- The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be paid in Indian currency.

Explanation.- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purpose of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act, 1962.

[F. No. 354/178/2016-TRU]

ANURAG SEHGAL, Under Secy.